Website: www.winews.in | Email: winews.in@gmail.com | दिल्ली, नोएडा, हापुड़, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रूड़की, हरिद्वार, देहरादून, मुरादाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा,राजस्थान, पंजाब, बहराइच,रामपुर, लखनऊ, काशीपुर, देवबंद में प्रसारित

दैनिक

वेलकम इंडिया

गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

RNI NO. UPHIN/2018/76874

नये भारत की नई सोच

वर्ष: 07 अंक: 323 | शनिवार, 28 नवम्बर-2026 (गाजियाबाद) | पेज-8 | मूल्य-एक रुपया

सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला- घोषणाएं करने से पहले उन्हें अपने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए

बताएं जब वे सत्ता में थे, तब युवाओं, किसानों, महिलाओं और प्रदेश के विकास के लिए क्या किया: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- पहचान का संकट पैदा करने वाले लोग फिर युवाओं के पास प्रमाणपत्र लेकर पहुंचने का प्रयास करेंगे : मुख्यमंत्री





वेलकम इंडिया, नेटवर्क

गोंडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत देवीपाटन मंडल के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के 46,800 छात्र-छात्राओं एवं प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंगेरीलाल के सपने दिखाने से विकास नहीं होता। विकास के लिए समय, समर्पण और स्पष्ट विजन चाहिए। पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश को माफिया और उपद्रव प्रदेश बनाकर युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज वही उत्तर प्रदेश माफिया, कर्फ्यू और दंगा मुक्त होकर देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन रहा है। जिनकी सोच केवल परिवार तक सीमित थी, उन्होंने सैफई तक सोचा, जबकि हमारी सरकार ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर उसकी तकदीर बदलने के लिए पूरी ताकत लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह टैबलेट केवल एक डिजिटल डिवाइस नहीं, बल्कि युवाओं के लिए चलता-फिरता विश्वविद्यालय है। इसके माध्यम से उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास के नए अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस तकनीक का उपयोग अपने भविष्य को संवारने में करें। रील देखने में 30 सेकंड लगाएं, लेकिन अपने कौशल को निखारने के लिए प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट जरूर दें। टैबलेट के साथ सपनों और संकल्पों को भी हमेशा चार्ज रखिए। सपने बड़े होने चाहिए, उसके अनुरूप परिश्रम की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप चार्ज रहेंगे तभी असुरीय शक्तियां और नेगेटिव फोर्सेज डिस्चार्ज होंगी।

कभी गोंडा देश का सबसे गंदा शहर, आज विकास की नई पहचान

मुख्यमंत्री ने गोंडा और देवीपाटन मंडल के पुराने हालात का उल्लेख करते हुए कहा कि 2017 से पहले गोंडा का नाम देश के सबसे गंदे शहरों में आया था। देवीपाटन शक्तिपीठ तक पहुंचने वाली सड़कें बेहद खराब थीं। बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जैसे जिले विकास की दौड़ में इतने पीछे थे कि नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की सूची में एक ही मंडल के तीन जनपद शामिल थे। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से भी ये जिले प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में गिने जाते थे। लेकिन, आज गोंडा में मेडिकल कॉलेज बन चुका है। बहराइच में मेडिकल कॉलेज संचालित है। बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से चल रहा है।

2047 के विकसित भारत के सारथी बनेंगे आज के युवा

मुख्यमंत्री ने युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल होना चाहिए। मतदान अधिकार के साथ नैतिक कर्तव्य भी है। युवा साथी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है। उस समय आज के युवा ही देश और प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। जब युवा अपनी ऊर्जा और प्रतिभा के साथ आगे बढ़ेंगे तो नकारात्मक शक्तियां कमजोर होंगी और 2047 का उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर एवं विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित होगा।

18 हजार से अधिक पाठ्यक्रम, स्कॉलरशिप से स्टार्टअप तक एक क्लिक पर जानकारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि युवा साथी ऐप के माध्यम से टैबलेट में 18 हजार से अधिक शैक्षिक कंटेंट और निशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। छात्र-छात्राएं एक क्लिक पर छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह डिवाइस युवाओं को नौकरी तलाशने के साथ डिजिटल उद्यमी बनने में भी मदद करेगा। आईआईएम लखनऊ की स्टडी में सामने आया कि इन उपकरणों के माध्यम से तीन करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से सक्षम होने में मदद मिली। लेकिन, ध्यान रखें कि एआई आपको सशक्त बनाने वाला उपकरण होना चाहिए, न कि दिमाग पर हावी होने का माध्यम। हर वायरल कंटेंट सही नहीं होता, इसलिए किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले फैक्ट चेक करें और डिजिटल सुरक्षा का ध्यान रखें। इस टैबलेट से फीड नहीं, अपना फ्यूचर स्क्रॉल करिए।

वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया से नो कर्फ्यू-नो दंगा तक की यात्रा

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जर्जर थी। स्कूलों में भवन और शिक्षकों का अभाव था तथा नकल, भूमि, खनन, शराब और वन माफिया पूरे सिस्टम पर हावी थे। पिछली सरकारों की एक ही उपलब्धि थी- वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया। आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है। अब यूपी में 'नो कर्फ्यू, नो दंगा-यूपी में सब चंगा' की स्थिति है। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन कायाकल्प और प्रोजेक्ट अलंकार का उल्लेख करते हुए कहा कि स्कूलों और इंटर कॉलेजों के जर्जर भवनों को नए स्वरूप में विकसित किया गया है।

एनडीए सरकार ने परिसीमन विधेयक संशोधनों को दी मंजूरी, लोकसभा सीटें 50% बढ़ेंगी



वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, विधेयक में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, इन संशोधनों में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में एक समान 50% की वृद्धि करने का प्रावधान है। साथ ही, सदन में प्रत्येक राज्य के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को तय करने के लिए 1971 की जनगणना के इस्तेमाल पर लगी रोक को और 25 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार का यह कदम कई दक्षिणी राज्यों द्वारा उठाई गई एक प्रमुख मांग को पूरा करता है।

प्रस्तावित परिसीमन विधेयक से लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत, लोकसभा में सीटों की संख्या मौजूदा 550 से बढ़कर अधिकतम 850 तक हो सकती है। परिसीमन प्रक्रिया में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण और इस प्रक्रिया के लिए अपनाए गए ढांचे के आधार पर सीटों का आवंटन तय करना शामिल होता है।

इस प्रस्ताव ने राजनीतिक चिंताएं पैदा कर दी हैं, खासकर दक्षिणी राज्यों की पार्टियों के बीच। उन्होंने सवाल उठाया है कि इस प्रक्रिया से संसद में उनके प्रतिनिधित्व पर क्या असर पड़ सकता है।

यह बहस अब महिला आरक्षण को लागू करने और जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व तथा जनसंख्या नियंत्रण में प्रगति करने वाले राज्यों के हितों के बीच संतुलन बनाने के व्यापक सवाल से भी गहराई से जुड़ गई है।

परिसीमन विधेयक क्या है?

परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि मौजूदा जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। यह प्रक्रिया एक स्वतंत्र 'परिसीमन आयोग' द्वारा संवैधानिक प्रावधानों (जिनमें अनुच्छेद 81, 82 और 170 शामिल हैं) के अंतर्गत पूरी की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व लगभग संतुलित रहे। साथ ही, इसके जरिए अनुसूचित जातियों (रउ) और अनुसूचित जनजातियों (रळ) के लिए आरक्षित सीटों के आवंटन की भी समीक्षा की जाती है। प्रस्तावित 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक' का उद्देश्य लोकसभा की सदस्य संख्या और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों के बंटवारे से जुड़े प्रावधानों में बदलाव करना है। इसके मुख्य प्रस्तावों में से एक निचले सदन (लोकसभा) की अधिकतम सदस्य संख्या को बढ़ाना है। मौजूदा संवैधानिक ढांचे के अनुसार, लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। प्रस्तावित संशोधन के तहत इस सीमा को बढ़ाकर 850 सदस्य करने का प्रस्ताव है, जिसमें राज्यों के लिए अधिकतम 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें होंगी।

यूपी चुनाव जीतने के लिए लाया जा रहा परिसीमन विधेयक

सपा प्रमुख अखिलेश का बीजेपी पर हमला

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि प्रस्तावित परिसीमन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ''सबसे बड़ी भूल'' साबित होगी और दावा किया कि इस कवायद का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को प्रभावित करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में परिसीमन से जुड़े नये महिला आरक्षण विधेयक को संभवतः मंजूरी दे दी गई और इसे अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में इस विधेयक को मंजूरी के लिए पेश किया गया। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल ने कुछ संशोधनों के साथ इसे मंजूरी दे दी। इन संशोधनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन के बाद लोकसभा में किसी भी राज्य की हिस्सेदारी अन्य राज्यों की तुलना में कम न हो। यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''परिसीमन भाजपा की सबसे बड़ी भूल होगी।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''जब उन्हें लगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव उनके हाथ से निकल रहे हैं, और चंदा चोरी तथा श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी के विवाद के बाद, उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने और पूरे देश को गुमराह करने के लिए परिसीमन लाने की शुरूआत कर दी।'' यादव ने कहा कि नोटबंदी सहित भाजपा सरकार द्वारा लिए गए कई बड़े फैसले अपेक्षित लाभ नहीं दे पाए। उन्होंने 2016 की नोटबंदी के दौरान जन्मे एक बच्चे का जिक्र करते हुए कहा, ''आज भी हम खजांची का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान हुआ था।'' यादव ने कहा, ''सरकार ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप और हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार कितने गुना बढ़ गया है।'' सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के केंद्र के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। यादव ने कहा, हमें भरोसा दिलाया गया था कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और कोई भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा।



कार्तिगई दीपम विवाद में सुप्रीम कोर्ट सख्त, तमिलनाडु के मुख्य सचिव और डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी

वेलकम इंडिया, नेटवर्क



नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु में कार्यपालिका द्वारा अपने राजनीतिक आकाओं के निदेशों पर कार्रवाई किए जाने को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), मदुरै के जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किये। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के न्यासी मंडल को निलंबित कर दिया और निर्देश दिया कि शनिवार को उच्चिपिल्लैयार मंडपम में प्रज्वलित दीप की लौ से तिरुपरनकुंद्रम स्थित दीपथून पर दीप प्रज्वलित किया जाए। यह कार्रवाई 20 नवंबर को कार्तिगई दीपम के संबंध में दिए गए शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन करने को लेकर की गई। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर के न्यासी मंडल को निलंबित किया और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को रिसीवर नियुक्त किया, साथ ही मंदिर और तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी की सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को सौंप दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय से कहा कि तमिलनाडु सरकार ने उसके अधिकारियों को विवादित दीपथून स्तंभ पर कार्तिगई दीपम के पास जाने की अनुमति नहीं देकर अदालत की ''घोर अवमानना'' की है। पीठ ने कहा कि संवैधानिक अराजकता पैदा करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को वह रास्ते पर लाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि मंदिर के न्यासियों ने एएसआई को सूचित किया था कि उसके अधिकारियों के प्रवेश के संबंध में उन्हें उच्चाधिकारियों से कोई निर्देश नहीं मिला था। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान कहा, ''मेरी विनम्रतापूर्वक दलील है कि यह अदालत की घोर अवमानना और प्रशासनिक अहंकार का मामला है। सरकार शुरू से ही इसका विरोध करती रही है।'' मेहता ने दलील दी कि अवमानना के आरोपियों की दलीलें सुनने से पहले दीपथून पर दीप प्रज्वलित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''एएसआई की ओर से मेरा अनुरोध है कि चूंकि यह स्वीकार किया जा चुका है कि आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है, इसलिए अवमानना के आरोपियों की दलीलें सुनने से पहले उन्हें दीप प्रज्वलित कराकर अवमानना से बचना चाहिए।''

मोदी सरकार संविधान बदलने की कोशिश में: कांग्रेस



नई दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटें बढ़ाकर संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस, विपक्षी दलों के साथ मिलकर इसका पूरी ताकत से विरोध करेगी। लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने पार्टी के संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक के बाद शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि इस संबंध में कांग्रेस का रुख पहले से ही स्पष्ट है कि लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या को बरकरार रखा जाए और इसी के आधार पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए तथा लोकसभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात अगले 25 साल तक कायम रखा जाए।

गैंग वार@ मिलन ढाबा: रोहतक में आधी रात को अंधाधुंध फायरिंग में 4 मरे, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

वेलकम इंडिया, नेटवर्क



रोहतक। हरियाणा के रोहतक में 26 नवंबर की दरमियानी रात एक ऐसी खूनी वारदात हुई, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। दिल्ली-हिसार रोड पर खरावड़ बाईपास के पास स्थित मिलन ढाबे पर रात करीब 12:30 से 1 बजे के बीच हथियारबंद हमलावरों ने खाना खा रहे चार युवकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं। हमलावर गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे थे और उनका निशाना ढाबे की एक टेबल पर बैठे युवक थे। अचानक हुई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गई। तीन युवकों की मौत खाने की टेबल पर ही हो गई, जबकि जान बचाने के लिए पहली मंजिल की ओर भागे चौथे युवक का हमलावरों ने पीछा किया और उसे भी गोलियों से छलनी कर दिया। हैरानी की बात यह है कि वारदात खरावड़ पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई। शुरूआती जांच में पुलिस इसे दो प्रतिद्वंद्वी गैंगों के बीच पुरानी रंजिश का नतीजा मानकर जांच कर रही है। वहीं विपक्ष ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार को घेर लिया है। जहां तक घटनाक्रम की बात है तो आपको बता दें कि घड़ी की सुइयां रात के करीब एक बजे का वक्त बता रही थीं। मिलन ढाबे पर कुछ लोग खाना खा रहे थे। तभी हथियारबंद हमलावर गाड़ियों में सवार होकर वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि पांच से छह हमलावरों ने मौके पर पहुंचते ही गोलियां चलानी शुरू कर दीं। निशाना सीधे उन युवकों पर था जो एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। अचानक हुई फायरिंग से ढाबे पर मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कोई टेबल के पीछे छिपा तो कोई कुर्सियों की आड़ लेकर अपनी जान बचाने लगा। हमलावरों की गोलियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। तीन युवक टेबल पर ही गोलियों का शिकार होकर गिर पड़े। लेकिन मौत का यह खेल यहीं नहीं रुका। चौथा युवक जान बचाने के लिए ढाबे की पहली मंजिल की तरफ भागा। उसे लगा कि शायद ऊपर पहुंचकर हमलावरों की नजरों से बच जाएगा। मगर हमलावरों ने उसका पीछा किया। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे और वहां भी उसे गोलियों से भून दिया। इसके बाद हथियार लहराते हुए हमलावर मौके से फरार हो गए। मृतकों की पहचान रिंकू, विनीत और हर्ष उर्फ यश के रूप में हुई है। तीनों झज्जर जिले के डीघल गांव के रहने वाले थे। चौथा मृतक हिमांशु झज्जर के बेरी क्षेत्र का निवासी था। पुलिस के मुताबिक हिमांशु बीए का छात्र था और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। शुरूआती जांच में यह आशंका भी जताई गई है कि वह गलत पहचान का शिकार हुआ। यानी हमलावरों का निशाना कोई और था, लेकिन गोलियों की इस अंधी बारिश में एक ऐसे युवक की भी जान चली गई, जिसका कथित गैंगवार से सीधा संबंध होने की जानकारी सामने नहीं आई है। उधर, जांच की दिशा अब हरियाणा के दो चर्चित गैंगों के बीच पुरानी दुश्मनी की तरफ घूम रही है। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे हिमांशु भाऊ और सन्नी रिटोलिया से जुड़े गुटों की आपसी रंजिश हो सकती है। मृतक रिंकू के रिश्तेदार और शिकायतकर्ता मन्नू ने आरोप लगाया है कि रिंकू, विनीत और हर्ष सन्नी रिटोलिया के संपर्क में थे और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया।

संपादक की कलम

रोटी की जमीन छीनकर रोशनी बाँटने का कैसा संकल्प



ललित शर्मा
संपादक

जब विकास का जुलूस खेतों से होकर गुजरता है, तो सबसे पहले फसलें सहम जाती हैं और किसानों के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगते हैं। बांका की भितिया की उपजाऊ जमीन पर आज यही स्थिति दिखाई दे रही है। एक ओर सत्तर हजार करोड़ रुपये का एमओयू, अट्ठाईस सौ मेगावाट बिजली उत्पादन का वायदा और बिहार को ऊर्जा-समृद्ध बनाने का दावा है, तो दूसरी ओर वे खेत हैं, जिनकी मिट्टी ने पीढ़ियों से धान और गेहूँ उगाकर परिवारों का जीवन सँवारा है। अब उन्हीं खेतों पर परमाणु रिएक्टर की छाया पड़ने की आशंका है। यह विवाद केवल जमीन अधिग्रहण का नहीं, बल्कि विकास की उस अवधारणा पर सवाल है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा के नाम पर उपजाऊ कृषि भूमि और पर्यावरण की कीमत नजरअंदाज की जा रही है। सरकार का तर्क है कि बिहार को बिजली, उद्योग और रोजगार के नए अवसर चाहिए। इस आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। दशकों से ऊर्जा की कमी और औद्योगिक पिछड़ेपन से जूझते राज्य को विकास की नई राह चाहिए। लेकिन क्या इसकी पूर्ति का एकमात्र रास्ता उपजाऊ कृषि भूमि पर परमाणु संयंत्र स्थापित करना है? भितिया की जमीन केवल मिट्टी का भूखंड नहीं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रस्तावित संयंत्र की सालाना सोलह करोड़ घन मीटर पानी की जरूरत गंभीर चिंता पैदा करती है। आसपास के कुओं, नहरों और सिंचाई पर इसका क्या असर पड़ेगा? चांदन जलाशय की क्षमता 157 एमसीएम से घटकर करीब 56 एमसीएम रह गई है। ऐसे में जल उपलब्धता के सरकारी दावों और वास्तविक परिस्थितियों के बीच अंतर पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कुल 160 एमसीएम पानी चांदन और बदुआ जलाशयों से (80-80 एमसीएम) लिया जाना प्रस्तावित है। कमी की स्थिति में गंगा से पाइपलाइन के जरिए पूरक आपूर्ति की शर्त भी जुड़ी है। फिर भी आधिकारिक आकलनों में पानी की उपलब्धता पर्याप्त बताई जा रही है, जबकि जलाशयों की वास्तविक क्षमता और मौसमी निर्भरता पर सवाल बने हुए हैं। जब धरातल पर जलसंकट मौजूद है, तब आंकड़ों के भरोसे इतनी बड़ी परियोजना का भविष्य कैसे सुरक्षित माना जा सकता है? पटना की सड़कों पर किसान और मजदूर जब विरोध मार्च निकालते हैं, तो उनकी आवाज केवल मुआवजे तक सीमित नहीं होती। उनके प्रतिरोध में जमीन, आजीविका, अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचाने की चिंता समाहित है। उनका सवाल है—क्या हमारी रोटी की कीमत बिजली के बिल से भी कम आँकी जाएगी? संयुक्त किसान मोर्चा की अठारह सूत्रीय मांगों में सबसे प्रमुख मांग उपजाऊ कृषि भूमि पर प्रस्तावित परमाणु संयंत्र रद्द करने की है। लोकतंत्र में जनभावनाओं की सुनवाई तभी सार्थक है, जब सत्ता उन्हें विरोध का शोर मानकर खारिज न करे। मुआवजे और पुनर्वास के आश्वासन बड़ी परियोजनाओं के साथ अक्सर दिए जाते हैं, लेकिन विस्थापन की पीड़ा किसी आर्थिक पैकेज से नहीं भर सकती। जमीन छूटने पर किसान केवल संपत्ति नहीं खोता, बल्कि अपनी पहचान, सामाजिक जड़ें और पीढ़ियों से जुड़ा जीवन भी खो देता है। विस्थापित व्यक्ति न पूरी तरह शहर का हो पाता है, न अपने उजड़े गाँव का रह जाता है। यही वजह है कि किसानों की चिंता को केवल मुआवजे की मांग मानना उनके संघर्ष और भविष्य के सवालों को सीमित कर देना होगा। परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कार्बन उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम होना इसकी बड़ी विशेषता है, लेकिन स्वच्छता का मूल्यांकन केवल धुएँ और कार्बन उत्सर्जन से नहीं किया जा सकता। रेडिएशन का संभावित खतरा, परमाणु अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान और दुर्घटना की आशंका भी गंभीर कसौटियाँ हैं।

भारतीय खाद्य संस्कृति पर आघातों से सुप्रीम कोर्ट

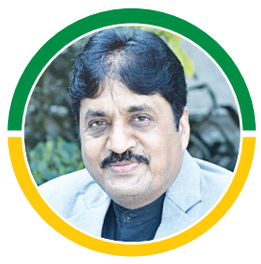

ललित गर्ग
लेखक



भारत की पहचान केवल उसकी आध्यात्मिकता, विविधता और संस्कृति से नहीं, उसकी रसोई से भी होती है। हमारी रसोई में स्वाद के साथ स्वास्थ्य, ऋतु के साथ संतुलन और भोजन के साथ संस्कार जुड़े रहे हैं। दादी-नानी के हाथों का भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, वह परिवार की सेहत की पहली पाठशाला था। दाल, बाजरा, ज्वार, रागी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, छाछ, अंकुरित अनाज, मसालों का संतुलित उपयोग और घर का ताजा भोजन भारतीय जीवन-पद्धति की ताकत रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमारी थाली धीरे-धीरे बदल गई है। स्वाद के नाम पर बाजार ने हमारी रसोई में प्रवेश किया और सुविधा के नाम पर पैकेट ने घर की कड़ाही को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसी बदलती खाद्य संस्कृति के बीच सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्देश एक महत्वपूर्ण चेतावनी की तरह सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य पैकेटों पर फ्रंट-ऑफ-पैक पोषण लेबलिंग को मजबूत करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अधिक शुगर, सैचुरेटेड फैट और नमक वाले उत्पादों पर अलग-अलग स्पष्ट चेतावनी चिह्न हों। न्यायालय ने 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को प्रमुखता से दिखाने तथा 'हाई शुगर', 'हाई फैट और 'हाई साल्ट' जैसे स्पष्ट संकेत देने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है- उपभोक्ता को वह जानकारी सामने मिले, जिसे वह छोटे अक्षरों में खोजते-खोजते अक्सर छोड़ देता है।

यह फैसला केवल लेबल बदलने का फैसला नहीं है, यह उस सोच को बदलने का प्रयास है जिसमें चमकदार पैकेट देखकर भोजन की गुणवत्ता तय कर ली जाती है। आज बाजार में किसी उत्पाद का विज्ञापन उसकी पौष्टिकता से अधिक आकर्षक पैकेजिंग, स्वाद और सुविधा बेचता है। बच्चे रंगीन पैकेट से आकर्षित होते हैं, युवा त्वरित भोजन को जीवनशैली समझने लगे हैं और व्यस्त परिवारों के लिए डिब्बाबंद भोजन समय बचाने का आसान विकल्प बन गया है। समस्या तब पैदा होती है जब सुविधा धीरे-धीरे आदत और आदत बीमारी में बदल जाती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि भोजन का अर्थ बदल रहा है। भोजन कभी जीवन को पोषण देने की प्रक्रिया था, अब वह तेजी से उपभोग की वस्तु बन रहा है। अधिक नमक, अधिक चीनी और अधिक वसा हमारे स्वाद की इंद्रियों को तो संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन शरीर की जरूरतों को नहीं। स्वाद की जीभ छोटी अवधि की खुशी चाहती है, जबकि शरीर दीर्घकालिक संतुलन मांगता है। बाजार ने हमारी जीभ को जीतने की कोशिश की है, अब हमें अपने विवेक को जीतना होगा। भारत जैसे देश में यह चुनौती और गंभीर है, क्योंकि यहां भोजन केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, संस्कृति का हिस्सा है। हमारी परंपरा में 'जैसा अन्न वैसा मन' की धारणा रही है। भोजन को आयु, ऋतु, प्रकृति और श्रम के अनुरूप लेने की परंपरा थी। भारतीय रसोई में अनेक ऐसे खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें आज दुनिया 'सुपरफूड' कहकर खोज रही है। बाजरा, जौ, दालें, तिल, मूंगफली, विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां और स्थानीय खाद्य परंपराएं हमारी अपनी विरासत हैं। विडंबना यह है कि जिन खाद्य पदार्थों की ओर दुनिया स्वास्थ्य के लिए लौट रही है, हम उन्हीं को छोड़कर अत्यधिक प्रसंस्कृत और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पहल को केवल उपभोक्ता अधिकार का विषय मानना पर्याप्त नहीं होगा। इसे भारतीय खाद्य संस्कृति के पुनर्जागरण के अवसर के रूप में देखना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी भी यहां बहुत बड़ी है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल यह सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए कि उत्पाद खाने योग्य है, यह भी देखना होगा कि उपभोक्ता को उस उत्पाद के वास्तविक स्वास्थ्य प्रभाव की जानकारी आसानी से मिले। एफएसएसएआई को वैज्ञानिक, स्पष्ट और उपभोक्ता-केंद्रित नियम बनाने होंगे। केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं, उनका प्रभावी निरीक्षण और कठोर पालन भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इसी दिशा में नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने का अवसर देता है। लेकिन सारी जिम्मेदारी सरकार या अदालत की नहीं हो सकती। उपभोक्ता को भी अपनी थाली का प्रहरी बनना होगा। जिस प्रकार हम घर खरीदते समय कीमत, स्थान और गुणवत्ता देखते हैं, उसी प्रकार भोजन खरीदते समय उसके घटकों को देखना भी हमारी आदत बननी चाहिए। किसी पैकेट पर बड़ा 'हेल्दी' लिखा होना उसे स्वतः स्वस्थ नहीं बना देता। विज्ञापन स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र नहीं है। असली प्रमाण उसके पोषण संबंधी विवरण और हमारी आवश्यकता के बीच संतुलन है। बच्चों के मामले में विशेष सावधानी आवश्यक है। बच्चे विज्ञापन और पैकेजिंग से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं। यदि स्कूल के आसपास और डिजिटल माध्यमों पर अत्यधिक चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य पदार्थों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता रहेगा, तो स्वस्थ भोजन उनके लिए 'उबाऊ' और अस्वास्थ्यकर भोजन 'मजेदार' बन जाएगा। इसलिए स्कूलों को केवल पाठ्यपुस्तकों में स्वास्थ्य शिक्षा देने के बजाय कैंटीन और परिसर के आसपास उपलब्ध भोजन के माध्यम से भी स्वस्थ आदतें विकसित करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के आसपास ऐसे खाद्य पदार्थों और उनके विज्ञापनों पर नियंत्रण की दिशा में भी जोर दिया है। हमें यहां एक और क्रांतिकारी विचार पर काम करना होगा-'फूड लिटरेसी' को जनशिक्षा का हिस्सा बनाना। जिस तरह बच्चों को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता सिखाई जा रही है, उसी तरह उन्हें खाद्य साक्षरता भी सिखाई जानी चाहिए। बच्चे जानें कि शुगर क्या करती है, अधिक नमक क्यों नुकसान पहुंचाता है, संतृप्त वसा क्या है, पैकेट पर लिखे पोषण-लेबल को कैसे पढ़ना है और ताजा स्थानीय भोजन क्यों बेहतर विकल्प हो सकता है। एक जागरूक बच्चा केवल स्वयं स्वस्थ नहीं रहेगा, वह अपने परिवार की भोजन-आदत भी बदल सकता है। साथ ही भारतीय खाद्य संस्कृति को आधुनिक रूप देकर पुनर्जीवित करने की जरूरत है। स्वस्थ भोजन का अर्थ यह नहीं कि स्वाद छोड़ दिया जाए। भारत के पास स्वाद और स्वास्थ्य का अद्भुत संतुलन बनाने की हजारों वर्ष पुरानी क्षमता है। जरूरत है कि बाजरा, दाल, सब्जियों, पारंपरिक पेयों और स्थानीय व्यंजनों को आधुनिक प्रस्तुति, स्वच्छ पैकेजिंग और उचित मूल्य के साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। हमें विदेशी खाद्य संस्कृति का विरोध नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध खाद्य संस्कृति को इतना आकर्षक बनाना है कि भारतीय युवा उसे गर्व से अपनाए। इस दिशा में एक नया सामाजिक अभियान चल सकता है-'मेरी थाली, मेरी जिम्मेदारी।'

संसद में सियासी महासंग्राम: 850 सीटें, महिला आरक्षण और 2029 का चुनावी गणित!



किशन भावनानीं
लेखक



वैश्विक स्तरपर वर्तमान वैश्विक प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्रांति,कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आंकड़ा आधारित नीति निर्धारण के दौर में दुनियाँ के लोकतांत्रिक देश अपनी संसदों में कानून बनाते समय नवीनतम जनसंख्या आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और भविष्य की आवश्यकताओं को आधार बना रहे हैं। अमेरिका की सीनेट और प्रतिनिधि सभा से लेकर ब्रिटेन तथा यूरोप की संसदीय व्यवस्थाओं तक बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नीतिगत निर्णय लेने की परंपरा दिखाई देती है। इसी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की संसद का आगामी विशेष सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक संवैधानिक और लोकतांत्रिक घटनाक्रम बन गया है।केंद्र सरकार ने लोकसभा को सोमवार 30 नवंबर 2026 और राज्यसभा को बुधवार 2 दिसंबर 2026 से पुनःबैठाने का निर्णय लिया है।दोनों सदनों की बैठकें क्रमशः 30 नवंबर और 1 दिसंबर तथा 2 और 3 दिसंबर तक चल सकती हैं।संसदीय कार्यमंत्री ने 26 नवंबर को आवश्यक सरकारी कामकाज का हवाला दिया था,जबकि 27 नवंबर को उन्होंने यह भी कहा कि इस सत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक और राष्ट्रीय महत्व के विषय सामने आ सकते हैं। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र बताना चाहूंगा कि हालांकि शुक्रवार दिनांक 27 नवंबर 2026 तक शाम 6 बजे तक सरकार ने विधायी कार्यसूची में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण संबंधी प्रस्तावों को औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया है।इसके बावजूद राजनीतिक चचाओं के केंद्र में यही दोनों विषय हैं। साथियों बात अगर हम पहला महत्वपूर्ण पहलू,विशेष सत्र या मानसून सत्र का विस्तार? को समझने की करें तो इस घटनाक्रम की एक संवैधानिक और संसदीय बारीकी समझना जरूरी है।संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त 2026 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन उसे औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया था।इसलिए,आगामी बैठकें उसी सत्र के दूसरे भाग के रूप में आयोजित होने की बात सामने आई है। इसीलिए,इसे राजनीतिक और समाचार विमर्श में विशेष बैठक कहा जा रहा है, लेकिन तकनीकी रूप से इसे पूरी तरह अलग नया सत्र मानना सही नहीं होगा। सरकार ने सामान्य शीतकालीन सत्र की बजाय यह संक्षिप्त कार्यक्रम क्यों चुना,इसपर विपक्ष सवाल उठा रहाहै।वहीं सत्ता पक्ष आवश्यक सरकारी कामकाज को इसका कारण बता रहा है। सदन की अधिसूचित कार्यसूची और कार्यवाही का कार्यक्रम सटीकता से निर्णायक होगा। साथियों बात अगर हम दूसरा पहलू,543 से 850 सीटों तक लोकसभा का विस्तार !को समझने की करें तो प्रस्तावित संविधान संशोधन का सबसे बड़ा आकर्षण लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से बढ़ाकर 850 तक करने की संभावना है।वर्तमान लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें हैं।प्रस्तावित व्यवस्था में सीटों का विस्तार करके राज्यों के प्रतिनिधित्व का पुनर्गठन करने की चर्चा है।तर्क है कि 1952 में जब भारत का पहला आम चुनाव हुआ था,तब मतदाताओं की संख्या लगभग 17 करोड़ थी और लोकसभा में 489 सदस्य थे।आज मतदाताओं की संख्या लगभग 98 करोड़ पहुंच चुकी है,लेकिन निर्वाचित लोकसभा सीटें 543 ही हैं।ऐसे में बढ़ती आबादी और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व आवश्यकताओं को देखते हुए सीटें बढ़ाना समय की मांग बताया जा रहा है।हालांकि 850 सीटों का आंकड़ा प्रस्तावित अधिकतम सीमा है, कोई अंतिम स्वीकृत सीट आवंटन नहीं। प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, यह विधायी प्रावधानों और परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। साथियों बात अगर हम तीसरा पहलू,1971 की जनगणना बनाम 2027 की जनगणना का सवाल! को समझने की करें तो परिसीमन विधेयक के तहत राज्यों के बीच सीटों के अनुपात को 1971 की जनगणना पर स्थिर रखने(25 वर्षों के लिए और बढ़ाने) और राज्यों के भीतर सीटों के पुनर्गठन के लिए 2011 की जनगणना का उपयोग करने का प्रस्ताव है।इसनिर्णय और 1971 बनाम 2027 की जनगणना के पीछे के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं (अ)1971 की जनगणना को आधार बनाने के प्रमुख कारण,दक्षिणी राज्यों की चिंताओं का समाधान (संघीय संतुलन):मीडिया रिपोर्टों के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तमिलनाडु,केरल और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है।यदि नई जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीटें बांटी जातीं, तो उत्तर भारत के तेजी से बढ़ती आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ जातीं और दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाता। 50 प्रतिशत समान वृद्धि का फॉमूर्ला: इस असंतुलन को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की सीटों में एकसमान 50प्रतिशत वृद्धि करने और 1971 की जनगणना के अनुपात को अगले 25 वर्षों (2051 तक) के लिए फ्रीज (स्थिर) रखने का फॉमूर्ला तैयार किया है। इससे लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़कर 850 (815 राज्यों से और 35 केंद्र शासित प्रदेशों से) करने का रास्ता साफ होगा और किसी भी राज्य की हिस्सेदारी कम नहीं होगी।अप्रैल 2026 की विफलता से सबकः अप्रैल 2026 में जब सरकार ने बिना इस संवैधानिक गारंटी के परिसीमन विधेयक पेश किया था तब विपक्ष के विरोध के कारण यह लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत (298 पक्ष में, 230 विरोध में) हासिल नहीं कर सका था।(ब)2027 की जनगणना का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा? 2029 के चुनाव में महिला आरक्षण लागू करनाः 2023 में पारित 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' (106वां संविधान संशोधन) के तहत लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए जनगणना और परिसीमन की शर्त रखी गई थी।समय की बाध्यताः आगामी जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 तय है। यदि इस जनगणना के पूरे होने और उसके आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाती,तो 2029 के आम चुनावों तक महिला आरक्षण लागू करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता।2011 की जनगणना का उपयोगः समय बचाने और 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से, प्रस्तावित संशोधन के तहत 2027 की जनगणना का इंतजार किए बिना पहले से प्रकाशित 2011 की जनगणना के आधार पर राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। साथियों बात अगर हम चौथा पहलू,महिला आरक्षण और 2029 का राजनीतिक लक्ष्य ! को समझने की करें तो, सितंबर 2023 में संसद ने 106वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके क्रियान्वयन को संबंधित जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। सरकार की मंशा इस व्यवस्था को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की बताई जा रही है। अप्रैल 2026 में इसी उद्देश्य से संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 तथा संबंधित विधायी प्रस्ताव सामने आए थे। सरकार का तर्क था कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन और लोकसभा की सीटों के पुनर्गठन को एक साथ जोड़ना आवश्यक नहीं है। महिलाओं को मौजूदा सीटों में भी सटीकता से आरक्षण दिया जा सकता है।

असली दौलत

मदिरा की रूतवा

कविता



जग में मदिरा की रुतवा है कमाल ।
हलक में उतर जाये तो,कराता बवाल ।।
दरिद्रनारायण समझे,खुद को धनवान ।
मूरख भी बन जाता है नशे में ज्ञानवान ।।

पीने वाला बन जाता पल का बादशाह ।
खुद को बताता है ये शाही का शांहशाह ।।
मच्छर तन बन जाये मैदान में पहलवान ।
कोई नहीं होता इनके आगे गुणवान ।।

मस्त चाल है मस्ती का है सरकार ।
नशा गिरा देता नाली में इनको बार बार ।।
भाषण देता है बन कर बड़ा विद्वान ।
इनके आगे जग के सारे मानव। नादान ।।

भूखा ही सो जाता शराबी का बाल गोपाल ।
नशे की हालत में ना होता है खुद का ख्याल ।।
शराबी को होता है शराब से गहरा प्यार ।
चाहे भाँड़ में चला जाये इनका परिवार ।।

नशा ने कर दी है घर की। हालात बुरा हाल ।
फिर भी पीने वाला करता पड़ोस में धमाल ।।
हर एक से लड़ने को बन्दा है आज तैयार ।
चाहे मिट जाये खुद की खुद से, है लाचार ।।

अदालतों को भी समझनी होगी अपनी लक्ष्मण रेखा



डॉ. सत्यवान सौरभ
लेखक



न्यायपालिका लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था की ताकत उसके अधिकारों के विस्तार में नहीं, बल्कि उनके मर्यादित और निष्पक्ष इस्तेमाल में होती है। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना निश्चित रूप से गंभीर मामला है। यदि सरकारी अधिकारी ही अदालतों के निदेर्शों को ठेंगे पर रखने लगें तो कानून के शासन का क्या अर्थ रह जाएगा? लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या किसी न्यायाधीश को अपने आदेश की अवहेलना होते ही किसी अधिकारी को तत्काल अवमानना का दोषी ठहराने का अधिकार मिल जाता है? क्या न्यायिक नाराजगी ही कानूनी अपराध का प्रमाण बन सकती है? सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों ने इसी खतरनाक प्रवृत्ति पर सवाल उठाते हुए न्यायिक अधिकारों की सीमा याद दिलाई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 और 215 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बचाना, न्यायिक आदेशों का सम्मान सुनिश्चित करना और न्याय प्रशासन में बाधा डालने वालों पर अंकुश लगाना है। लेकिन न्यायालय की अवमानना का कानून किसी न्यायाधीश के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा का हथियार नहीं है। यह न्यायिक संस्था और न्याय प्रक्रिया की गरिमा बचाने का संवैधानिक माध्यम है। दोनों के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। अदालत की अवमानना मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। दीवानी अवमानना में न्यायालय के आदेश, निर्देश, निर्णय या दिए गए आश्वासन की जानबूझकर अवहेलना शामिल है। विजय माल्या को वर्ष 2022 में अवमानना के मामले में सुनाई गई सजा इसका उदाहरण है। वहीं आपराधिक अवमानना में न्यायालय को बदनाम करने वाली ऐसी अभिव्यक्ति, जो न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करे, न्याय प्रशासन में बाधा डाले अथवा न्यायिक कार्यवाही को बाधित करे, शामिल होती है। प्रशांत भूषण का वर्ष 2020 का मामला इसी श्रेणी में चर्चित रहा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायपालिका की आलोचना करना अपराध है। लोकतंत्र में न्यायाधीशों के निर्णयों पर सवाल उठाना, न्यायिक व्यवस्था की कमियों पर चर्चा करना और संस्थागत जवाबदेही की मांग करना नागरिकों का अधिकार है। आलोचना और अवमानना के बीच की रेखा इतनी धुंधली नहीं होनी चाहिए कि असहमति को ही अपराध बना दिया जाए।

हालिया विवाद बिहार के रोहतास जिले से जुड़ा है, जहां एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पुलिस अधीक्षक को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। निर्देश का पालन नहीं होने पर न्यायिक अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को तलब किया और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 384 के तहत अवमानना का दोषी ठहराते हुए एक रुपये का सांकेतिक जुमार्ना लगा दिया। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा तो वहां इस कार्रवाई के कानूनी आधार पर ही सवाल खड़े हो गए। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत के आदेश का पालन न करना और अदालत के सामने अवमानना करना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी अधिकारी द्वारा पहले दिए गए न्यायिक आदेश का पालन नहीं करना अपने आप में न्यायालय के सामने किया गया अपराध नहीं बन जाता। पीठ ने न्यायिक अधिकारी को अपनी शक्तियों की सीमा समझने की सलाह दी और बाहुबली की तरह व्यवहार न करने की नसीहत भी दी।

यह टिप्पणी केवल एक न्यायिक अधिकारी के आचरण पर सवाल नहीं है, बल्कि पूरी न्यायिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। न्यायाधीश होना अधिकारों का खुला लाइसेंस नहीं है। अदालत का आदेश बाध्यकारी जरूर है, लेकिन आदेश की अवहेलना पर कार्रवाई भी निर्धारित कानून के अनुसार ही होनी चाहिए। न्यायिक अधिकारिता और व्यक्तिगत नाराजगी के बीच अंतर मिटने लगे तो न्याय की निष्पक्षता प्रभावित होना तय है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 384 न्यायालय को कुछ विशेष अपराधों के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाने का अधिकार देती है। इनमें न्यायालय के सामने प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करना, शपथ लेने से मना करना, दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश की अवहेलना करना और न्यायिक कार्यवाही में जानबूझकर अपमान या बाधा उत्पन्न करना जैसे अपराध शामिल हैं। इस प्रक्रिया के तहत अधिकतम एक हजार रुपये का जुमार्ना लगाया जा सकता है। लेकिन इस सीमित शक्ति का इस्तेमाल न्यायालय के किसी भी पुराने आदेश की अवहेलना को दंडित करने के लिए नहीं किया जा सकता। कानून ने अधिकार दिया है तो उसकी सीमा भी तय की है। न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस सीमा का सम्मान करना ही होगा।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब न्यायाधीश ही कानून की प्रक्रिया को दरकिनार करने लगें तो आम नागरिक न्याय किससे मांगेगा? किसी अधिकारी की गलती पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन क्या न्यायिक अधिकारी को भी यह अधिकार है कि वह अपनी नाराजगी को तत्काल दंड में बदल दे? न्यायालय में मौजूदगी के दौरान किए गए अपमान और किसी पुराने आदेश के अनुपालन में हुई देरी को एक ही तराजू में नहीं तौला जा सकता। यदि हर आदेश की अवहेलना पर निचली अदालतें संक्षिप्त अवमानना की कार्रवाई करने लगें तो न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर असंगतियां पैदा हो सकती हैं।

इसका अर्थ यह कतई नहीं कि पुलिस अधीक्षक या अन्य प्रशासनिक अधिकारी न्यायालयों के आदेशों को नजरअंदाज करें। सरकारी पद और वर्दी किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाते। अदालत के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए उचित कानूनी रास्ता अपनाना होगा। परिस्थितियों के अनुसार ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना की कार्यवाही के लिए उठाया जा सकता है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक ललित कुमार द्वारा वेलकम इंडिया प्रिन्टर्स, 1/26, साउथ साइड, जी टी रोड़, गाजियाबाद-201001 से मुद्रित कराकर ग्राउन्ड फ्लोर , दुर्गा टॉवर, आर.डी.सी राजनगर, गाजियाबाद 201002 से प्रकाशित किया । संपादक : ललित शर्मा
सम्पर्क सूत्रः 9891116568

किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा गाजियाबाद न्यायालय में ही होगा।

2027 विस चुनाव: जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने प्रतापगढ़ की तीन सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी

विजय द्विवेदी/वेलकम इंडिया

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। इसी क्रम में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने प्रतापगढ़ जनपद में अपनी चुनावी तैयारियों को गति देते हुए जिले की तीन विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने गुरुवार को प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। पार्टी की इस घोषणा के बाद प्रतापगढ़ की राजनीति में चुनावी हलचल तेज होने के आसार हैं। घोषित प्रत्याशियों के अनुसार, कुंडा विधानसभा सीट से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह स्वयं चुनाव मैदान में उतरेंगे। बाबागंज विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक एवं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से पार्टी के लखनऊ मंडल प्रभारी कुलदीप पटेल को प्रत्याशी घोषित किया गया है।

तीन सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर पार्टी ने स्पष्ट की रणनीति

पार्टी नेतृत्व की ओर से प्रत्याशियों के चयन को लेकर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। तीन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी शुरूआती रणनीति सामने रख दी है। पार्टी ने जहां अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताया है, वहीं विश्वनाथगंज सीट से संगठन में जिम्मेदारी निभा रहे कुलदीप पटेल को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। कुंडा विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से रघुराज प्रताप सिंह की राजनीतिक पहचान और प्रभाव का प्रमुख केंद्र रहा है। वह वर्ष 1993 से



लगातार इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अब तक सात बार विधायक चुने जा चुके हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कुंडा से उनकी उम्मीदवारी को पार्टी की महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा माना जा रहा है। बाबागंज विधानसभा सीट से पार्टी ने वर्तमान विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष विनोद सरोज को प्रत्याशी बनाया है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। पार्टी नेतृत्व ने आगामी चुनाव के लिए एक बार फिर विनोद सरोज को उम्मीदवार बनाकर उन पर भरोसा जताया है। विनोद सरोज को संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी को पार्टी के संगठनात्मक नेतृत्व और विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सक्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। विश्वनाथगंज विधानसभा सीट से कुलदीप पटेल को प्रत्याशी घोषित करना पार्टी की इस बार की चुनावी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुलदीप पटेल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक में लखनऊ मंडल के प्रभारी हैं। उनकी पत्नी माधुरी पटेल वर्तमान में प्रतापगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं।

कुलदीप पटेल सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ शैक्षणिक क्षेत्र से भी जुड़े हैं। वह परमेश्वर प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज, मालाधर छत्ता के प्रधानाचार्य हैं। उनका स्थानीय स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि के रूप में भी अनुभव रहा है। वर्ष 2010 में वह मालाधर छत्ता से क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसके बाद वर्ष 2015 में इसी ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान भी चुने गए। पंचायती राज व्यवस्था से लेकर संगठनात्मक जिम्मेदारी तक का अनुभव रखने वाले कुलदीप पटेल को विश्वनाथगंज से उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक उपस्थिति मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

2022 की जीत को दोहराने की चुनौती

गौरतलब है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने प्रतापगढ़ की कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह और बाबागंज से विनोद सरोज विधायक निर्वाचित हुए थे। अब 2027 के चुनाव के लिए पार्टी ने इन दोनों सीटों पर अपने मौजूदा विधायकों को दोबारा उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं विश्वनाथगंज में कुलदीप पटेल को उतारकर तीसरी सीट पर भी चुनावी दावेदारी पेश कर दी है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रतापगढ़ में तीन सीटों पर प्रत्याशियों की समय से घोषणा करना जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की चुनावी तैयारियों का अहम कदम है। इससे घोषित उम्मीदवारों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में संगठन, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए समय मिलेगा।

अन्य सीटों पर भी नजरें

प्रतापगढ़ जनपद की कुल सात विधानसभा सीटों में से फिलहाल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने तीन सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। जिले की शेष विधानसभा सीटों को लेकर पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। फिलहाल कुंडा, बाबागंज और विश्वनाथगंज में प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी राजनीतिक तैयारी का संकेत दे दिया है। आने वाले समय में पार्टी का संगठनात्मक विस्तार, चुनावी गतिविधियां और अन्य सीटों पर होने वाली घोषणाएं प्रतापगढ़ के राजनीतिक समीकरणों को किस दिशा में ले जाएंगी, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी।

सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग में अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स फेस्ट 2026-27 के दूसरे दिन खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

वेलकम इंडिया/हरेंद्र शर्मा

हापुड़। जनपद के पिलखुवा स्थित अनवरपुर गांव में सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हापुड़ में आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स फेस्ट 2026-27 (जोनल स्तरीय प्रतियोगिताझजोन-5, पश्चिमी उत्तर प्रदेश) के दूसरे दिन विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन उत्साह, उमंग और खेल भावना के साथ किया गया। तीन दिवसीय इस खेल महोत्सव में 45 नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हुए अपनी खेल प्रतिभा, शारीरिक क्षमता और उत्कृष्ट प्रदर्शन का परिचय दिया। दूसरे दिन बैडमिंटन के सेमीफाइनल, वॉलीबॉल के रोमांचक मुकाबले तथा बास्केटबॉल के सेमीफाइनल मैच आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं, एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर एवं 800 मीटर दौड़, रिले रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद और डिस्कस थ्रो जैसी स्पधाओं का आयोजन किया गया। सभी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने पूरे जोश, अनुशासन और प्रतिस्पर्धात्मक भावना के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल मैदान में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए टीम मैनेजर, शिक्षकगण, खेल अधिकारी एवं अन्य सहयोगी सदस्य उपस्थित रहे। विभिन्न कॉलेजों के प्रतिभागियों के बीच आपसी सहयोग, एकता, अनुशासन और खेल भावना का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला।









यह खेल महोत्सव अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉ. जे. रामचंद्रन के मार्गदर्शन एवं संरक्षण तथा वाइस चेयरपर्सन डॉ. रम्या रामचंद्रन के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस आयोजन का सफल संचालन सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हापुड़ की प्राचार्या प्रो. (डॉ.) आर. पिरामिला के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस खेल महोत्सव का मुख्य उद्देश्य नर्सिंग विद्यार्थियों में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना, आपसी सम्मान और खेल भावना को प्रोत्साहित करना है। साथ ही, विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध कराना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 45 कॉलेज, एक मंच और खेल भावना का एक साझा जुनून इस आयोजन की विशेष पहचान बनकर उभरा है। दूसरे दिन की सफल प्रतियोगिताओं के बाद अब सभी की निगाहें खेल महोत्सव के अंतिम दिन पर टिकी हैं, जहां विभिन्न स्पधाओं के विजेताओं और चैंपियनों के नाम सामने आएंगे। सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हापुड़ इस प्रतिष्ठित जोनल स्तरीय खेल महोत्सव की मेजबानी करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। संस्थान ने विश्वविद्यालय, सभी प्रतिभागी कॉलेजों, टीम मैनेजरों, खेल अधिकारियों, शिक्षकगण, स्वयंसेवकों एवं आयोजन में सहयोग देने वाली सभी टीमों के प्रति आभार व्यक्त किया।

विकास कार्यों में गुणवत्ता का रखें विशेष ध्यान, जनप्रतिनिधियों को भी दें जानकारी: केपी मलिक

वेलकम इंडिया/हरेंद्र शर्मा

हापुड़। जनपद के प्रभारी मंत्री केपी मलिक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रभारी मंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति और पिछली बैठक में दिए गए निदेर्शों पर की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद में चल रहे सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा कार्यों की जानकारी समय से जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जनपद में जो भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उनमें जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। विकास कार्यों का जनप्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण भी कराया जाए, जिससे कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि



सरकार की मंशा के अनुरूप विकास योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए और निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक में प्रभारी मंत्री ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद की सभी गौशालाओं में सर्दी से बचाव के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। गौशालाओं में हरे चारे, भूसे और स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि गोवंश को ठंड के मौसम में किसी प्रकार की परेशानी न हो। प्रभारी मंत्री ने समाज कल्याण अधिकारी से वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन न मिलने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया कि पेंशनरों की केवाईसी और अन्य जानकारियां अपडेट होने के कारण पेंशन रुकी हुई थी। प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की प्रगति की जानकारी भी प्राप्त की। प्रभारी मंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। वर्तमान में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या को देखते हुए सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि मरीजों को उपचार के लिए परेशानी न उठानी पड़े।

उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जाए। सरकार की ओर से बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का लाभ समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। प्रभारी मंत्री ने गढ़ गंगा मेले के सफल आयोजन के लिए जनपद के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पूरी आयोजन टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनपद में संचालित सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। साथ ही निमार्णाधीन और पूर्ण हो चुके सभी विकास कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य दी जाए। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने बैठक में जनप्रतिनिधियों की ओर से उठाई गई समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी समीक्षा बैठक से पहले सभी समस्याओं का जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह से जनपद की कानून व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की।

भाकियू (एकता शक्ति) ने जनसमस्याओं को लेकर एसडीएम सिकंदराबाद को सौंपा ज्ञापन, एक सप्ताह का दिया अल्टीमेटम

वेलकम इंडिया/राजेंद्र सिंह

बुलंदशहर। भारतीय किसान यूनियन (एकता शक्ति) के पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष एमएस भाटी एवं जिलाध्यक्ष मजदूर सभा बुलंदशहर नीरज कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर एसडीएम सिकंदराबाद को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने दो प्रमुख समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उठाया। पहली समस्या ककोड़ क्षेत्र में कथित रूप से अवैध तरीके से किए जा रहे मकानों एवं निर्माण कार्यों की है। संगठन ने मामले की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।वहीं दूसरी समस्या सिकंदराबाद क्षेत्र में संचालित आरा मशीनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की उठाई गई। संगठन का कहना है कि आरा मशीनों के शोर के कारण आसपास के मोहल्लों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



इस मामले में भी जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।संगठन ने प्रशासन को एक सप्ताह का समय देते हुए दोनों मामलों में जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि निर्धारित समय सीमा में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर भारतीय किसान यूनियन (एकता शक्ति) तहसील सिकंदराबाद में धरना-प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन की होगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री एडवोकेट अक्षित शर्मा, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रमोद नेता, हरिओम प्रधान, युवा पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष विपिन त्यागी, नोएडा महानगर अध्यक्ष सतीश पंडित, तहसील अध्यक्ष दादरी ब्रज किशोर नागर, स्याना ब्लॉक उपाध्यक्ष हनी त्यागी, नोएडा महानगर महासचिव केतन पंडित, युवा प्रदेश सचिव हरिओम शर्मा सहित संगठन के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गेहूं की फसल में दीमक का प्रकोप, बचाव के लिए बीज उपचार जरूरी: गौरव प्रकाश

वेलकम इंडिया/हरेंद्र शर्मा

हापुड़। जिले में गेहूं की फसल में दीमक कीट का प्रकोप किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दीमक फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक नुकसान पहुंचा सकती है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को बुवाई से पहले बीज उपचार करने और खेत में दीमक की रोकथाम के लिए उचित उपाय अपनाने की सलाह दी है। दीमक मिट्टी में रहने वाला सर्वभक्षी कीट है, जो पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें नष्ट कर देता है। प्रभावित खेत की मिट्टी खोदने पर दीमक के घर देखे जा सकते हैं। बुवाई के बाद शुरूआती अवस्था में और कभी-कभी फसल की परिपक्वता के समय भी दीमक का प्रकोप देखने को मिलता है। यह पौधों की जड़ों और बढ़ते तनों को नुकसान पहुंचाती है। इससे पौधे सूख जाते हैं और आसानी से जमीन से उखाड़े जा सकते हैं। किसानों को गेहूं की बुवाई के दौरान



पूरी तरह सड़ी और सूखी गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करना चाहिए। खेत में समय-समय पर खरपतवारों का नियंत्रण भी जरूरी है। बुवाई से पहले बीज को ब्यूवेरिया बेसियाना जैव कीटनाशी से उपचारित करना दीमक की रोकथाम में सहायक है। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज में 8 से 10 ग्राम जैव कीटनाशी पाउडर मिलाएं। इसे हल्के गुड़ के घोल के साथ मिलाकर बीज पर अच्छी तरह चिपकाएं और लगभग 30 मिनट तक छायादार स्थान पर रखने के बाद बुवाई करें।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए 28 व 29 नवंबर को विशेष अभियान

वेलकम इंडिया संवाददाता

हापुड़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत हापुड़ जनपद में 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जिले के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष शिविर आयोजित कर मतदाता सूची में नाम शामिल करने, अपात्र नामों को हटाने और मतदाता विवरण में संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य जांच लें तथा पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने में सहयोग करें।

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली के आलेख्य प्रकाशन के बाद पंजीकरण से छूटे हुए नागरिकों, पहली बार मतदान करने



वाले युवाओं तथा अन्य पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान शनिवार, 28 नवंबर और रविवार, 29 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस दौरान सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदेय स्थलों पर आवश्यक अभिलेखों और प्रपत्रों के साथ उपस्थित रहेंगे। विशेष अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 तथा नाम, पता या अन्य प्रविष्टियों में संशोधन के लिए फार्म-8 प्राप्त किए जाएंगे। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए पात्र नागरिक अपने संबंधित बीएलओ, तहसील कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय, हापुड़ से फार्म-6 प्राप्त कर सकते हैं। नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाले नागरिकों को आवेदन के साथ अपनी नवीनतम फोटो, जन्मतिथि और निवास से संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर उपलब्ध है तो उसे भी साथ लेकर आएं। फार्म-6 भरते समय नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड सहित पता सही-सही दर्ज करना और आवश्यक अभिलेखों एवं नवीनतम फोटो को अपलोड करना जरूरी है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने अथवा संशोधन के लिए नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के ECINET मोबाइल ऐप, Voter Helpline ऐप और आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in का उपयोग किया जा सकता है। मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए संबंधित बीएलओ के पास उपलब्ध निर्वाचक नामावली के अलावा https://electoralsearch.eci.gov.in / वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकता है। वहीं, नाम, पता या अन्य प्रविष्टियों में संशोधन के लिए फार्म-8 संबंधित बीएलओ के पास जमा कर रसीद प्राप्त करें। दोनों फार्म ऑनलाइन माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने हापुड़ जनपद के समस्त निर्वाचकों से अपील की है कि वे विशेष अभियान की तिथियों का लाभ उठाते हुए निर्वाचक नामावली में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम जांच लें। जिन पात्र नागरिकों के नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें। साथ ही अपने रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों और परिचितों को भी इस अभियान के प्रति जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सकें और निर्वाचक नामावली को त्रुटिविहीन बनाया जा सके।

एसपी मधुबन कुमार ने पेश की मानवता की मिसाल, घायल छात्राओं को तत्काल पहुंचाया अस्पताल

वेलकम इंडिया/राजेंद्र सिंह

हापुड़। दिल्ली रोड स्थित सबली कट के पास शुक्रवार को एक स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसमें सवार दो छात्राएं घायल हो गईं। इसी दौरान पुलिस कार्यालय जाते समय एसपी हापुड़ मधुबन कुमार की नजर घायल छात्राओं पर पड़ी। उन्होंने तत्काल अपना वाहन रुकवाकर छात्राओं को प्राथमिक उपचार दिलाया और अपने एस्कॉर्ट वाहन से उन्हें नजदीकी अस्पताल भिजवाया।इस दौरान एसपी मधुबन कुमार ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए कहा कि पुलिस का काम केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि मुसीबत के समय आमजन की मदद करना भी है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना हमारा मानवीय कर्तव्य है। पुलिस सदैव जनता की सुरक्षा, सेवा और सहायता के लिए तत्पर है। एसपी



के इस सराहनीय मानवीय कार्य की लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत के समय आम नागरिकों के साथ खड़े होना भी उसका महत्वपूर्ण दायित्व है। पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार की इस संवेदनशील पहल से न केवल घायल छात्राओं को समय पर सहायता मिली, बल्कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास का रिश्ता भी मजबूत हुआ। उनके इस मानवीय व्यवहार की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे कार्यों से पुलिस की सकारात्मक छवि समाज में और मजबूत होती है तथा आमजन में सुरक्षा और सहयोग का भाव पैदा होता है।

आपदा के समय त्वरित राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री धामी

प्रथम आपदा प्रबंधन दिवस पर मुख्यमंत्री ने की चार महत्वपूर्ण घोषणाएं, आवासीय अग्निकांड को आपदा मानकर मिलेगा मुआवजा

/ओपी उनियाल





देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपदा की सूचना मिलते ही पूरा तंत्र सक्रिय होना चाहिए और प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत एवं सहायता पहुंचनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में आपदा प्रभावितों के बीच जाकर उनके साथ खड़े रहना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने यह बात सचिवालय, देहरादून में प्रथम आपदा प्रबंधन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कही। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन प्रदेश के लिए निरंतर चुनौतीपूर्ण विषय है। राज्य को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपदाओं के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ ही प्रत्येक स्तर पर पूर्व तैयारियों को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश ने अनेक आपदाओं का सामना किया है। इस दौरान शासन-प्रशासन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने बेहतर समन्वय के साथ त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस तथा अन्य वर्दीधारी सेवाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों को आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके सहयोग से आम जनमानस को आपदाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन में जनसहभागिता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रशिक्षित लोगों की सहायता से आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम चरण में अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रति एक हजार विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को राज्य सरकार द्वारा आपदा मित्र अथवा आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षित शिक्षक छात्र-छात्राओं को आपदाओं के प्रति निरंतर जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन से जोड़कर उन्हें आपात परिस्थितियों के प्रति तैयार करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि आवासीय भवनों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण आग लगने की घटना को आपदा के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ऐसे अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के मानकों के अनुरूप राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही आपदाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं के दौरान निःस्वार्थ भाव से राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) पुस्तिका एवं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) 2026-27 का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से जनहानि एवं नुकसान को कम किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गऊ ग्राम परखम में करेंगे कई प्रकल्पों को शिलान्यास और लोकार्पण, व्यवस्थाओं को दिया गया अंतिम रूप

वेलकम इंडिया संवाददाता



मथुरा/फरह। दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति के तत्वावधान में निर्मित विभिन्न प्रकल्पों का लोकार्पण एवं शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री योगी आदित्यनाथ कल (शनिवार) को दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, गऊ ग्राम, परखम, फरह में करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए गऊ ग्राम, परखम में तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल और सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। समिति द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य वीवीआईपी अतिथियों के आगमन को देखते हुए उनके स्वागत की तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री के उदबोधन के लिए मंच और पंडाल बनकर तैयार हो गया है। वीआईपी लोगों, पत्रकार, विशिष्ट अतिथियों और आगंतुकों के लिए अलग- अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को प्रातः 10 बजे से दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र गऊ ग्राम परखम फरह में पशु आयुर्वेद एवं पारंपरिक ज्ञान में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का विमोचन, अनुवादात्मक चिकित्सा में आयुर्वेद और पंचगव्य अनुसंधान केंद्र और श्री नंदीश्वर छात्रावास (विधार्थी छात्रावास) का लोकार्पण करेंगे। आयुर्वेद कॉलेज एवं चिकित्सालय और पशु चिकित्सालय महाविद्यालय एवं कर्मचारी आवासीय परिसर (2 बीएचके) का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास, भारत सरकार होंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे।

कार्यक्रम में परम पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामण्डलेश्वर डॉ. स्वामी कैलाशानंद गिरि जी महाराज और आचार्य महामण्डलेश्वर, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा श्री अवधेशानन्द गिरि जी महाराज का आशीर्वचन प्राप्त होगा। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुरेश सोनी अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होंगे। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रो. एस.पी. सिंह बघेल, केंद्रीय राज्यमंत्री, मत्स्य पालन एवं पशुपालन, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र 'दयालु' आयुष मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और धर्मपाल सिंह कैबिनेट मंत्री, पशुधन एवं दुग्ध विकास उपस्थित रखेंगे। इनके अलावा दिनेश कुलकर्णी अ.भा. संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ, डॉ. चिन्मय पंड्या, कुलाधिपति, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, प्रवीण रामदास राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री, विज्ञान भारती शामिल होंगे। दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, गऊ ग्राम, परखम, फरह को रंगाई- पुताई और साफ-सफाई कर तैयार कर दिया गया है। तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। कार्यक्रम मीडिया प्रभारी कीर्ति पी० कुमार ने बताया है कि कार्यक्रम के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

कोर्ट के आदेश पर हुए शिक्षकों के तबादले, बीएसए रतन कीर्ति पर उठ रहे सवालों के बीच सीडीओ ने किया स्थिति स्पष्ट

सीडीओ डॉ. पूजा गुप्ता बोलीं- न्यायालय के आदेश के क्रम में हुई तबादला प्रक्रिया, शिकायतों की जांच के लिए कमेटी गठित

वेलकम इंडिया संवाददाता



मथुरा। शिक्षकों के तबादलों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बीएसए रतन कीर्ति के पक्ष में एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों के तबादले न्यायालय के आदेश के क्रम में किए गए थे। सीडीओ के इस बयान से तबादला प्रकरण में बीएसए की भूमिका को लेकर चल रही चचाओं के बीच मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। दरअसल, जिले में शिक्षकों के तबादलों को लेकर पिछले कई दिनों से चचाएं चल रही हैं। तबादला प्रक्रिया पर कुछ लोगों की ओर से शिकायतें भी की गईं। इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने जांच कमेटी गठित की है। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बीएसए रतन कीर्ति को न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ था और उसी के क्रम में शिक्षकों के तबादले किए गए। उन्होंने यह भी बताया कि मामले में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। सीडीओ के बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि तबादलों के पीछे न्यायालय का आदेश एक महत्वपूर्ण आधार रहा है। ऐसे में जांच पूरी होने से पहले किसी भी प्रकार की अनियमितता को प्रमाणित मानना उचित नहीं होगा। अब जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे यह स्पष्ट होगा कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अपनाई गई प्रक्रिया पूरी तरह नियमानुसार थी या नहीं। फिलहाल, बीएसए रतन कीर्ति के संबंध में सामने आए सीडीओ के बयान ने पूरे प्रकरण को एक नया दृष्टिकोण दिया है। अब निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं।

बर्तन फेरी वाले से 16,200 रुपये की हुई लूट, मारपीट कर बाइक छोड़कर फरार हुए बदमाश



वेलकम इंडिया/मोहसिन रहमानी

कांधला। थाना क्षेत्र की नाला नहर पटरी पर बाइक सवार बदमाशों ने बर्तनों की फेरी कर लौट रहे युवक को रोककर मारपीट की और 16,200 रुपये की नकदी लूटकर फरार हो गए। बदमाश वारदात के दौरान अपनी एक बाइक मौके पर ही छोड़ गए। दिनदहाड़े हुई लूट की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया पुलिस ने मामले को मारपीट का बताते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है.शुक्रवार को जनपद हाथरस के गांव नगला बख्शी, तहसील सिकंदराराऊ निवासी अर्जुन पुत्र राजेश ने बताया कि वह अपने मामा मुकेश के साथ बर्तनों की फेरी करके वापस लौट रहा था।

आरोप है कि नाला नहर पटरी पर पहुंचने पर बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए दोनों के साथ मारपीट की और 16,200 रुपये की नकदी छीनकर फरार हो गए। बदमाश अपनी बाइक भी मौके पर छोड़ गए।सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक बच्चू सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बदमाशों की तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने मौके से बाइक कब्जे में लेकर पीड़ित की तहरीर पर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी बच्चू सिंह ने बताया कि मामले की सूचना मिली है, प्रथम जांच में मामला मारपीट का निकला है पुलिस जांच कर रही है जांच कर कार्रवाई की जाएगी ।

जिलाधिकारी ने डायट के प्रशिक्षुओ को वोट बढ़ाने के लिए किया जागरूक

वेलकम इंडिया संवाददाता



मथुरा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षु 2024,2025 एवं 2026 के डीएलएड प्रशिक्षुओं को स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान हेतु फार्म 6 भरने के लिए विशेष अभियान चलाया जिसमें जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह, स्वीप जनपद ऑर्डिनेटर सलोनी गौतम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट(आई ए एस)मथुरा,वरिष्ठ प्रवक्ता संजय डबराल,डायट स्वीप प्रभारी हिमांशु रावत प्रोफेसर दीनदयाल, प्रवक्ता मनीष दयाल, अध्यापक गुरु प्यारी सत्संगी एवं गोवर्धन के सह स्वीप प्रभारी अंकित अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्थान के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक गायन एवं नृत्य करके अधिक से अधिक युवाओं को अपना वोट बढ़ाने की अपील की जिसमें अधिक से अधिक फार्म 6 भर कर अपना योगदान विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 हेतु अपना वोट बढ़ाने के लिए किया जाए।डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मतदाता जागरूक के संबंध में रंगोली बनाई । जो कार्यक्रम का वह मुख्य आकर्षण रही।मिलन यादव,नम्रता मोना राठौर कमलेश कपिल, अमन , ललित प्रशिक्षुओं ने बैनर के माध्यम से समाज को अधिक से अधिक वोट करने और अपने 18 वर्ष से बड़े बच्चों का प्रथम बार मतदान हेतु नामांकन करने हेतु फॉर्म 6 भरवाने की अपील की। जगत सिंह,स्मृति शर्मा,तनुप्रिया और उमा वर्षा सैनी प्रशिक्षुओं द्वार द्वारा मतदान हेतु एवं मतदान में अपना सहयोग हेतु वोट बढ़ाने के लिए चार्ट और पोस्ट का निर्माण किया और उन्हें प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी मथुरा द्वारा संस्थान में प्रवेश के समय छवि शर्मा,एकता ज्योति,कल्पना संकल्प के साथ बुलंद आवाज में अधिक से अधिक वोट बढ़ाने के लिए संकल्प लिया और अपने वोट का अधिकार के बारे में जग जीवन को बताया। जिलाधिकारी द्वारा सरस्वती पर माल्यार्पण के बाद दीप्रज्वलन के बाद सभी प्रशियों को अधिक से अधिक नामावली में अपना नाम बढ़ाने हेतु फॉर्म 06 ऑनलाइन भरने के लिए अपील कि प्रत्येक प्रशिक्षु तीन ऐसे व्यक्तियों का भी फॉर्म 06 भरवाए जिनका आज तक नामावली में नाम नहीं है, इस चैन को बढ़ाया जाए एक तीन का नाम जोड़े के लिए फॉर्म 06 भरवाए और तीन 09 का व्यक्ति जोड़े इस चैन को जब तक आगे बढ़ानी है जब तक कोई भी व्यक्ति मतदान के नामांकन में अपनी सूची में नाम बढ़ने से रहना जाए हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अपने एक वोट की ताकत दिखाएं और अपने मनपसंद नेता को चुने डीएम ने सभी से आग्रह किया कि जिनके नाम मतदाता सूची में नाम नहीं है वह तत्काल ऑनलाइन या पोर्टल के माध्यम से या बीएलओ के माध्यम से अपना फार्म आज ही भरे जो व्यक्ति का अगर एक से अधिक जगह वोट है तो वे अपना फार्म 7 भरकर अपना नाम एक अन्य जगह से कटवा सकते हैं।फॉर्म 08 से संशोधन करवा सकते हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सलोनी गौतम ने प्रशिक्षुओं को मतदाता पंजीकरण, नाम जुड़वाने, संशोधन तथा निर्वाचन आयोग की ऑनलाइन सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने पात्र युवाओं को फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया भी समझाई।संस्थान से संजय डबराल,वरिष्ठ प्रवक्ता हिमांशु रावत डायट स्वीप प्रभारी संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता, शिखा शर्मा प्रवक्ता, नरेंद्र सिंह प्रवक्ता, रचना बाला प्रवक्ता के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें प्रशिक्षुओं रजनी, प्रिया स्नेहा चौहान कामिनी कुमारी द्वारा रंगोली और नुक्कड़ नाटक किया क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्रांजल शेखावत द्वितीय स्थान सचिन कुमार निमेष तृतीय स्थान रश्मि सारस्वत रही।

गंगेरू रोड पर नियमों को ताक पर रखकर चल रहा अल्ट्रासाउंड सेंटर

रेडियोलॉजिस्ट की गैरमौजूदगी में टेक्नीशियन कर रहा मरीजों की जांच, चौहान अल्ट्रासाउंड सेंटर की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

वेलकम इंडिया/मोहसिन रहमानी



कांधला। कस्बे के गंगेरू रोड पर संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। गंगेरू रोड स्थित चौहान अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कथित रूप से रेडियोलॉजिस्ट की अनुपस्थिति में टेक्नीशियन द्वारा मरीजों का अल्ट्रासाउंड किए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इस व्यवस्था को मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए संबंधित अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चौहान अल्ट्रासाउंड सेंटर पर नियमानुसार विशेषज्ञ चिकित्सक की मौजूदगी के बिना ही अल्ट्रासाउंड जांच की जा रही है। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं तो यह स्वास्थ्य संबंधी नियमों और मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मामला हो सकता है। स्थानीय व्यक्ति इस्तखार का कहना है कि अल्ट्रासाउंड एक महत्वपूर्ण चिकित्सकीय जांच है, जिसकी गुणवत्ता और रिपोर्ट की सटीकता मरीज के उपचार में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में जांच निर्धारित नियमों और योग्य विशेषज्ञ की देखरेख में ही होनी चाहिए। इस मामले को लेकर कस्बे के कई लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत भेजकर पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की है। शिकायतकताओं ने चौहान अल्ट्रासाउंड सेंटर के पंजीकरण, मान्यता, रेडियोलॉजिस्ट की उपलब्धता और वहां तैनात कर्मचारियों की योग्यता की जांच कराए जाने की मांग उठाई है। साथ ही आरोप सही मिलने पर संबंधित सेंटर के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि यदि किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर निर्धारित मानकों के विपरीत जांच की जा रही है तो विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं हो सकी। क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से समय-समय पर ऐसे सेंटरों का निरीक्षण किया जाता है या फिर नियमों की अनदेखी के बावजूद सेंटरों का संचालन हो रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए सेंटर का स्थलीय निरीक्षण कराया जाए। जांच के दौरान पंजीकरण संबंधी अभिलेखों, चिकित्सकीय स्टाफ की योग्यता और अल्ट्रासाउंड जांच की व्यवस्था का सत्यापन किया जाए, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

अनवार आलम की ताजपोशी पर छपिया छितौना में जश्न-ए-खुशी, मिठाइयां बांटकर समर्थकों ने मनाया गया जश्न

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनने पर गांव में खुशी की लहर



संतकबीरनगर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद पर अनवार आलम की नियुक्ति होते ही छपिया छितौना गांव में जश्न का माहौल बन गया। उनकी इस अहम जिम्मेदारी की खबर मिलते ही समर्थकों और चाहने वालों में उत्साह की लहर दौड़ गई। गांव में जगह-जगह मिठाइयां बांटी गईं और लोगों ने एक-दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर छपिया छितौना के ग्राम प्रधान डॉ. फिरोज अख्तर ने अनवार आलम को मिठाई खिलाकर बधाई दी। उन्होंने इस नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए इसे गांव और क्षेत्र के लिए सम्मान की बात बताया। अनवार आलम की नियुक्ति को लेकर समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने उम्मीद जताई कि उनके नेतृत्व में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा संगठन को नई मजबूती मिलेगी और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का काम और प्रभावी ढंग से होगा। इस अवसर पर अब्दुल सादिक, मोकीम अहमद, हीरालाल मौर्य, मकसूद आलम, नौशाद अहमद, अरबाज अहमद, मुमताज अहमद, अली अहमद, कलीम अहमद, शादाब अहमद, अब्दुल शाफी, आसादुल बारी, मोहम्मद अनस, फरहद अहमद,

दिशा की बैठक में विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर सांसद जगदंबिका पाल ने जताई नाराजगी

जर्जर बिजली तार बदलने और जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की मरम्मत कराने का दिया निर्देश





वेलकम इंडिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर। लोहिया कला भवन में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को समय से गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए गए। सांसद ने बैठक से अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोकने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने नए मजरों और टोलों में विद्युतीकरण के प्रस्ताव भेजने, जर्जर बिजली तार बदलने और ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने को कहा। आरडीएसएस योजना के कार्य समय से पूरा कराने के साथ जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण जनप्रतिनिधियों से कराया जाए। विधायक श्यामधनी राही ने तेतरी-सोहांस-लोटन मार्ग की खराब सड़क की मरम्मत कराने की मांग उठाई। सांसद ने काला नमक चावल की उत्पादकता, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए किसानों को जागरूक करने को कहा। बैठक में विधायक विनय वर्मा, सैय्यदा खातून, जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल, सीडीओ बलराम सिंह सहित जनप्रतिनिधि और जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

सड़क सुरक्षा पखवाड़ा: नियमों की अनदेखी पर 80 वाहनों का किया चालान, नौ सीज





वेलकम इंडिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत शुक्रवार को परिवहन विभाग ने जोगिया, बांसी और बर्डपुर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने, ट्रिपलिंग करने तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के मामलों में 80 वाहनों का चालान किया गया। वहीं, फिटनेस फेल दो और टैक्स बकाया होने पर सात वाहनों को निरुद्ध किया गया। अभियान के दौरान 10 ट्रालियों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप भी लगवाया गया, जिससे रात के समय उनकी दृश्यता बढ़ाई जा सके और दुर्घटनाओं की आशंका कम हो। एआरटीओ संजय कुमार सिंह ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क पर लापरवाही से बचने की अपील की।

20 साल की सेवा, फिर भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे रोजगार सेवक

मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर बुलंद की आवाज, ग्राम विकास सहायक बनाने की मांग



वेलकम इंडिया/मीनू बरकाती

पीलीभीत। ग्राम पंचायतों में पिछले करीब 20 वर्षों से कार्य कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की है। ग्राम रोजगार सेवक संघ एवं ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित मांगपत्र जिलाधिकारी के माध्यम से भेजकर समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई है। रोजगार सेवकों ने कहा कि वह लंबे समय से गांवों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मांगपत्र में कहा गया है कि ग्राम रोजगार सेवक पिछले दो दशकों से ग्राम पंचायतों में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार की ओर से समय-समय पर दिए गए कार्यों को भी पूरी जिम्मेदारी से संपन्न कराते हैं। अब वीबी-जी राम जी के अंतर्गत भी गांवों में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।रोजगार सेवकों ने अपनी प्रमुख मांगों में मानदेय न्यूनतम 24 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने और इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था करने की मांग की है। इसके साथ ही ग्राम रोजगार सेवकों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही गई है। मांगपत्र में एचआरए (मकान किराया भत्ता) नीति लागू करने की भी मांग उठाई गई है।इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास विभाग के सभी कार्यों को जॉब चार्ट में शामिल करते हुए ग्राम रोजगार सेवकों का पदनाम बदलकर ग्राम विकास सहायक किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।संघ की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि इन मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जनपद के ग्राम रोजगार सेवक प्रदेशव्यापी आंदोलन में शामिल होंगे। मांगपत्र में स्पष्ट किया गया है कि आगामी 3 दिसंबर 2026 को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। रोजगार सेवकों ने सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर उनकी समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है।अमानत रसूल, वृजनन्दन सिंह, रामगोपाल, राजकुमार सिंह,प्रदीप कुमार, आदेश राजपूत, वीरेंद्र सिंह, राजेश मौर्य, महताब गंगवार, अजय प्रताप सिंह. आर्य कुमार वर्मा, के.के. गौतम, ओंमकार, मनीष महेश्वरी, से उनकी डिग्रियां वर्षों से घरों की अलमारियों में रखी हुई हैं। स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में नौकरी मिलने तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये भत्ता मिलने से उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।युवाओं का कहना था कि अखिलेश यादव की यह योजना शिक्षित बेरोजगारों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इससे उन परिवारों को भी राहत मिलेगी, जिनके बच्चे उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। युवाओं ने कहा कि वे ऐसी नीतियां चाहते हैं, जिनमें शिक्षा के साथ रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता मिले।डॉ. रत्नेश गंगवार ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश के नौजवानों को बेहतर शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक भविष्य के अवसर मिलना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं, किसानों, गरीबों और वंचित वर्गों के हितों की बात करती रही है।उन्होंने कहा कि जनसंपर्क का उद्देश्य लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना और उनकी अपेक्षाओं को समझना है। गांवों में मिल रहे समर्थन और युवाओं के

बिलसंडा में युवाओं के बीच पहुंचकर डॉ. रत्नेश गंगवार ने बनाया माहौल

शिक्षित बेरोजगारों को पांच हजार रुपये भत्ते की उम्मीद ने पकड़ा जोर



वेलकम इंडिया/मीनू बरकाती

पीलीभीत। विधानसभा क्षेत्र बिलसंडा में समाजवादी पार्टी के नेता डॉ. रत्नेश गंगवार ने घर-घर पहुंचकर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों, युवाओं और विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा समाजवादी पार्टी की नीतियों और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की योजनाओं को लेकर चर्चा की। जनसंपर्क के दौरान युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। कई युवाओं ने उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही।जनसंपर्क के दौरान शिक्षित बेरोजगार युवाओं के बीच अखिलेश यादव की प्रस्तावित पांच हजार रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता योजना चर्चा का प्रमुख विषय रही। युवाओं ने कहा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी रोजगार नहीं मिलने

मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को किया जागरूक



वेलकम इंडिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

त्रिलोकपुर/सिद्धार्थनगर। शुक्रवार को मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के तहत थाना त्रिलोकपुर की मिशन शक्ति टीम ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़हरा बिशुनपुर में छात्राओं को महिला अपराध, साइबर अपराध से बचाव, दहेज उत्पीड़न और नए कानूनों की जानकारी देकर जागरूक किया। इस दौरान विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के पंपलेट भी वितरित किए गए। थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं को महिला सशक्तीकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में जानकारी दी गई। टीम ने आपात स्थिति में पुलिस सहायता के लिए 112, महिला हेल्पलाइन 1090 व 181, साइबर अपराध के लिए 1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सहित अन्य जरूरी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में बताया। इस दौरान उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार पांडेय, कांस्टेबल चंचल सरोज, महिला कांस्टेबल रूपा, विद्यालय प्रधानाध्यापक बब्बन प्रसाद यादव आदि मौजूद रहें।

बाल विवाह के खिलाफ एकजुट हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारी, पीलीभीत को इस कुप्रथा से मुक्त कराने का लिया गया संकल्प

शक्ति संवाद कार्यक्रम में बेटियों को किया जागरूक, 200 बच्चों को उपहार देकर बढ़ाया उत्साह



वेलकम इंडिया संवाददाता

पीलीभीत। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने और बेटियों को शिक्षा एवं सुरक्षित भविष्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को गांधी स्टेडियम स्थित गांधी प्रेक्षागृह में महिला कल्याण विभाग की ओर से अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस एवं शक्ति संवाद जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बाल विवाह के खिलाफ एकजुट होकर समाज को जागरूक करने का आह्वान किया।कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. दलजीत कौर, मरौरी ब्लॉक प्रमुख सभ्यता देवी वर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरुण क्रांति यशोदास, मुख्य विकास अधिकारी सतीश प्रसाद मिश्र सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी ने अतिथियों को पौधे भेंट कर स्वागत किया।इस दौरान अवंतीबाई और आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह के दुष्परिणामों को उजागर किया। शक्ति संवाद के तहत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थी बच्चों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संवाद कर अपने विचार साझा किए।नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें शिक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ब्लॉक प्रमुख सभ्यता देवी वर्मा ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है। सभी को मिलकर पीलीभीत को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. दलजीत कौर ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि अपने आसपास और रिश्तेदारी में कहीं भी बाल विवाह नहीं होने देंगे। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरुण क्रांति यशोदास ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए निर्धारित कानूनी आयु से पहले विवाह न कराने की अपील की।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 50 बच्चों को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के प्रतीक चिह्न वाले कॉफी मग, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के 100 बच्चों को लूडो तथा कोविड योजना के 50 बच्चों को थर्मस वितरित कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का संचालन दुर्गेश आर्या ने किया। अंत में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार जताया।

मतदाता सूची से नहीं छूटेगा किसी पात्र का नाम

डीएम आलोक कुमार ने बीएलओ को घर-घर सर्वे के दिए निर्देश



वेलकम इंडिया संवाददाता

पीलीभीत। विधानसभा निर्वाचन-2027 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को गांधी प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्र 127 पीलीभीत के बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की बैठक आयोजित की गई। इसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बीएलओ अपने-अपने बूथ क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करें। पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरवाएं। वहीं, मृतक एवं अपात्र मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में नाम, पता सहित अन्य विवरणों में संशोधन कराने के लिए फॉर्म-8 भरवाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।डीएम ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र नागरिक का नाम छूटना नहीं चाहिए। विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं, महिला मतदाताओं और अब तक सूची में शामिल होने से वंचित पात्र लोगों पर ध्यान दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।उन्होंने बीएलओ को निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रतिदिन कार्य करें और अपनी प्रगति की नियमित जानकारी उपलब्ध कराएं। प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और उसमें आवश्यक संशोधन कराने के प्रति जागरूक भी किया जाए।जिलाधिकारी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना बेहद जरूरी है। इसमें बीएलओ की भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी अधिकारी जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) प्रसून द्विवेदी सहित विधानसभा क्षेत्र 127 पीलीभीत के बूथ लेवल अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

मानदेय बढ़ाने समेत चार मांगों को लेकर रोजगार सेवकों ने किया धरना प्रदर्शन





वेलकम इंडिया/असदुल्लाह सिद्दीकी

सिद्धार्थनगर। मानदेय बढ़ाने समेत चार सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जुटे रोजगार सेवकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मांगों के निस्तारण की मांग की। धरने की अध्यक्षता जिला संयोजक सदानन्द यादव ने की। प्रदेश संयोजक कुलदीप द्विवेदी ने कहा कि रोजगार सेवक पिछले 20 वर्षों से गांवों में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो सेवा सुरक्षा मिली और न ही सम्मानजनक मानदेय। प्रदेश उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने कहा कि रोजगार सेवक श्रमिकों को काम दिलाने, मस्टररोल तैयार करने, जॉब कार्ड और विकास कार्यों की निगरानी जैसे कार्य करते हैं, फिर भी उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। ज्ञापन में मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह करने, भुगतान के लिए अलग बजट, रोजगार सेवकों और उनके परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा, एचआर पॉलिसी लागू करने तथा ग्राम पंचायत के सभी कार्यों को जॉब चार्ट में शामिल कर पदनाम ग्राम विकास सहायक करने की मांग की गई। जिला संयोजक सदानन्द यादव ने कहा कि मांगें पूरी होने तक कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी। तीन दिसंबर को प्रदेशव्यापी आह्वान पर लखनऊ में विधानसभा घेराव किया जाएगा। धरने का संचालन जिला संरक्षक राजेश चतुर्वेदी ने किया। इस दौरान जिला महामंत्री अमरेश यादव समेत बड़ी संख्या में रोजगार सेवक मौजूद रहे। रोजगार सेवकों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद लंबे समय से उनकी मांगों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांगों पर शीघ्र निर्णय लेकर रोजगार सेवकों के भविष्य को सुरक्षित करने की अपील की।

सफाई मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद बनी सहमति, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मिलेंगी अवकाश सहित अन्य सुविधाएं

राजीव मोंगरा/वेलकम इंडिया

सहारनपुर। नगर निगम में सफाई व्यवस्था और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों से जुड़ी समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ तथा अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी है। सहमति के अनुसार नगर निगम के सभी 58 वार्डों में सफाई व्यवस्था को पहले की तरह संचालित करने के लिए स्थायी एवं कार्यवाहक सफाई नायकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश और स्थानांतरण से संबंधित व्यवस्थाओं में भी बदलाव किया जाएगा। वार्ता में तय किया गया कि आउटसोर्सिंग सेवा नियम के तहत



सभी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों की आपूर्ति नगर निगम द्वारा आरआर कंपनी और सुकमा कंपनी के माध्यम से की जाएगी। सभी 58 वार्डों में नगर निगम के स्थायी सफाई नायक अथवा कार्यवाहक सफाई नायक नियुक्त किए जाएंगे। ये सफाई नायक नगर निगम के पूर्व से संचालित मस्टर रोल में आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों और वाहन चालकों की उपस्थिति दर्ज कराते हुए वार्डों की सफाई व्यवस्था का संचालन पहले की तरह करेंगे। कर्मचारियों की उपस्थिति का मस्टर रोल क्षेत्रीय सफाई निरीक्षक एवं मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा माह के अंत में पूर्व की भांति सत्यापित किया जाएगा। सहमति के अनुसार आउटसोर्सिंग सेवा नियमों का पालन करते हुए सफाई कर्मचारियों और वाहन चालकों को साप्ताहिक अवकाश, प्रसूति अवकाश सहित अन्य अनुमन्य अवकाश की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। स्थायी, संविदा और आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को उनकी मांग के अनुसार उनके निवास के निकटतम वार्ड में स्थानांतरित करने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा तय किया गया कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी को हटाने से पहले तीन बार नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद एक नोटिस डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। नगर स्वास्थ्य अधिकारी की सहमति मिलने के बाद ही संबंधित कर्मचारी को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर भी सहमति बनी है। वार्ता में बनी इन सहमतियों को सफाई कर्मचारियों के हितों और नगर निगम की सफाई व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रोडवेज बस की टक्कर से बुलेट सवार दरोगा की मौत परिवार में मचा कोहराम

वेलकम इंडिया संवाददाता

शिकारपुर। मेरठ-बदायूं हाईवे पर मां भगवती इंटरनेशनल स्कूल के निकट शुक्रवार देर शाम रोडवेज की टक्कर से बुलेट सवार दरोगा की मौत हो गई हादसे में जान गंवाने वाले दरोगा की पहचान राजवीर सिंह पुत्र जगत सिंह करीब 57 वर्ष के रूप में हुई है प्राप्त जानकारी के अनुसार दरोगा राजवीर सिंह बुलन्दशहर कोतवाली नगर में तैनात थे शुक्रवार को ड्यूटी समाप्त करने के बाद वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से डिबाई स्थित अपने बच्चों के पास लौट रहे थे इसी दौरान शिकारपुर क्षेत्र में मां भगवती इंटरनेशनल स्कूल के निकट उनकी बाइक रोडवेज बस से टकरा गई हादसे में उनकी मौत हो गई बताया जा रहा है कि तीन दिन पूर्व ही उनका डिबाई कोतवाली से बुलन्दशहर



कोतवाली नगर में स्थानांतरण हुआ था घटना की सूचना मिलते ही शिकारपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार, एसएसआई कस्बा इंचार्ज अमित कुमार, सहित भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी पुलिस का कहना है कि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाएगी साथ ही रोडवेज बस की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।

छुटमलपुर को मिला टैलेंटेड ईओ, अब रुकेगा नहीं विकास: विदाई में छलके आंसू, स्वागत में बिछे फूल

राजीव मोंगरा/वेलकम इंडिया

सहारनपुर। नगर पंचायत छुटमलपुर में शुक्रवार को एक भावुक और ऐतिहासिक पल देखने को मिला। एक तरफ टैलेंटेड और कर्मठ अधिकारी कमलाकांत राजवंशी की विदाई में लोगों की आंखें नम हो गईं, तो दूसरी तरफ नई ईओ नीलम पांडे के स्वागत में फूलों की बारिश हो गई। पर्व अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी अपने कार्यकाल में काम से जाने गए, नाम से नहीं। साफ-सफाई से लेकर विकास कार्यों तक, हर फाइल को समय पर निपटाना, हर गरीब की सुनना-यही उनकी पहचान रही। यही कारण है कि शासन ने उन्हें थाना भवन जैसे बड़े नगर पंचायत का चार्ज सौंपा है। अध्यक्ष शमा परवीन ने स्मृति चिन्ह भेंट कर कहा - ऐसा अधिकारी





किस्मत से मिलता है। नव नियुक्त अधिशासी अधिकारी नीलम पांडे भी टैलेंट और तेवर में किसी से कम नहीं हैं। पदभार संभालते ही उन्होंने साफ कह दिया अब छुटमलपुर में काम लटकेगा नहीं, दौड़ेगा। उन्होंने कहा कि साफ-सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, नाली-खड़ंजा और जनहित के हर काम को प्राथमिकता दी जाएगी। भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होगी। अध्यक्ष व सभासदों के सहयोग से छुटमलपुर को जिले की सबसे स्वच्छ और सुंदर नगर पंचायत बनाया जाएगा। समारोह में मौजूद लोगों का कहना था कि एक अच्छे अधिकारी की विदाई दुखद है, लेकिन नई अधिकारी के टैलेंट पर पूरा भरोसा है। अब नगर पंचायत में जनहित के कामों में तेजी आएगी और जनता को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष शमा परवीन, सुरेंद्र कुमार, योगेन्द्र कुमार, तुषार, अकुश कुमार आदि समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

न्यूनतम 24 हजार रुपये मानदेय और कैशलेस इलाज की मांग को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों ने सौंपा ज्ञापन

राजीव मोंगरा/वेलकम इंडिया

सहारनपुर। न्यूनतम 24 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय, कैशलेस चिकित्सा सुविधा और एचआर पॉलिसी लागू करने सहित चार सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ की जिला इकाई सहारनपुर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ग्राम रोजगार सेवकों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए मांगों का शीघ्र निस्तारण किए जाने की अपील की। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम रोजगार सेवक पिछले 20 वर्षों से ग्राम पंचायतों में पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने के साथ ही मनरेगा



(वीबी-जीआरएएमजी) के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बावजूद लंबे समय से कार्य करने के बाद भी ग्राम रोजगार सेवक मूलभूत सुविधाओं और सम्मानजनक मानदेय से वंचित हैं। संघ की ओर से मांग की गई कि ग्राम रोजगार सेवकों का न्यूनतम मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाए तथा इसके नियमित भुगतान के लिए पृथक बजट की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा ग्राम रोजगार सेवकों और उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द एचआर पॉलिसी लागू की जाए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के सभी कार्यों को उनके कार्यक्षेत्र में शामिल करते हुए पदनाम बदलकर 'ग्राम विकास सहायक' किया जाए। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि ग्राम रोजगार सेवक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। सरकार को उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए मांगों का शीघ्र समाधान करना चाहिए, ताकि वे और अधिक उत्साह एवं जिम्मेदारी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति दे सकें। इस मौके पर जिलाध्यक्ष घनश्याम सिंह राणा, प्रदेश सचिव एवं जिला संरक्षक जितेंद्र चौधरी, जिला महामंत्री नीटू चौधरी, जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार कश्यप, जिला संरक्षक रविंद्र राणा सहित सरसावा, नागल, नकुड़, बलियाखेड़ी और देवबंद आदि ब्लॉकों के अध्यक्ष तथा बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।

लंबित मांगों को लेकर एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने किया कार्य बंद आंदोलन

लंबित मांगों को लेकर एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने किया एक दिवसीय कार्य बंद आंदोलन

वेलकम इंडिया/संदीप तिवारी

वाराणसी/मुंबई। महाराष्ट्र राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृति समिति के निदेर्शानुसार श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी (एसएनडीटी) महिला विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर 26 नवंबर 2026 को एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बंद आंदोलन किया। इस आंदोलन के माध्यम से कर्मचारियों ने शासन का ध्यान लंबे समय से लंबित अपनी मांगों की ओर आकर्षित करते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग उठाई। कर्मचारियों का कहना है कि कई बार मांगों को शासन के समक्ष रखने और अनुस्मारक भेजने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृति समिति के अनुसार, राज्य के विभिन्न



विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारियों की अनेक महत्वपूर्ण मांगें लंबे समय से शासन स्तर पर लंबित हैं। इन मांगों को लेकर पूर्व में भी आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन शासन के अनुरोध का सम्मान करते हुए कर्मचारियों ने आंदोलन को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया था। उस समय आंदोलन के अगले चरण के संबंध में शासन को लिखित निवेदन के माध्यम से पूर्व सूचना भी दी गई थी। इसके बावजूद कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। समिति ने बताया कि लंबित मांगों को लेकर शासन को कई बार अनुस्मारक भेजे गए और लगातार अनुवर्ती कार्रवाई भी की गई, लेकिन सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। कर्मचारियों का मानना है कि उनकी मांगें सेवा सुविधाओं, आर्थिक सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इसी के चलते आंदोलन के अगले चरण के रूप में 26 नवंबर को एक दिवसीय सांकेतिक कार्य बंद आंदोलन आयोजित किया गया। शिक्षकेतर कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में 10:20:30 वर्ष की सेवांतर्गत आश्वासित प्रगति योजना लागू करना, राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करना, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करना तथा सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करना शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि इन मांगों पर निर्णय होने से उन्हें सेवा के दौरान बेहतर सुविधाएं और भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रभाकर पिळणकर, उपाध्यक्ष आनंद शिंदे एवं महासचिव प्रीतम कोकाटे के मार्गदर्शन में यह सांकेतिक कार्य बंद आंदोलन संपन्न हुआ। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता प्रदर्शित की और शासन से लंबित विषयों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। संयुक्त कृति समिति की ओर से शासन से मांग की गई कि शिक्षकेतर कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए उनकी चारों प्रमुख मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय किया जाए।

प्रगणक डिम्पल सचदेव को किया जायेगा सम्मानित

जनगणना ब्लॉक संख्या 019100 का बनाया बेहतरीन नक्शा

वेलकम इंडिया संवाददाता

सहारनपुर। जनगणना 2027 के लिए जोन एक अंतर्गत स्वगणना कार्य कर रही वार्ड 29 बेरीबाग क्षेत्र की प्रगणक डिम्पल सचदेव को उनके द्वारा किये गए श्रेष्ठ कार्य के लिए नगर निगम द्वारा सम्मानित किया जायेगा। डिम्पल सचदेव ने जनगणना ब्लॉक संख्या 019100 का नक्शा जोन इंचार्ज एवं जोनल अधिकारी जेपी यादव को भेंट किया है, जो किसी भी प्रगणक द्वारा अभी तक बनाया गया सबसे श्रेष्ठ नक्शा है। जोन एक प्रभारी/सहायक नगरायुक्त जे पी यादव ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि नगर क्षेत्र के प्रा.वि. हकीकत नगर की शिक्षा मित्र जनगणना-2027 के लिए प्रगणक के रुप में वार्ड 29 बेरी बाग में स्वगणना का कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्रगणक को अपने-अपने जनगणना ब्लॉक का नक्शा बनाना होता है। उन्होंने बताया कि प्रगणक डिम्पल सचदेव ने गणना



ब्लॉक संख्या 019100 का जो नक्शा बनाकर प्रस्तुत किया गया है, वह प्रंशसनीय और अनुकरणीय है।

उन्होंने बताया कि प्रगणक डिम्पल सचदेव ने गणना ब्लॉक का जो नक्शा बनाया है, वह बहुत सलीके और तरीके से बनाया गया है। नक्शे में मकानों, खाली प्लाटों, सड़कों, गलियों, वृक्षों, नदी, मंदिर, स्कूल, फैक्ट्री, दुकान, कच्ची सड़क, पक्की सड़क, हैंडपम्प आदि को अलग नंबरिंग करते हुए अलग-अलग रंगों और निशान के साथ दशार्या गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी प्रगणक द्वारा बनाया गया इतना स्पष्ट नक्शा देखने में नहीं आया है। जोनल अधिकारी यादव ने बताया कि प्रगणकों के प्रशिक्षण के दौरान श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रगणक को सम्मानित करने का एनाउंस किया गया था। उसी योजना के अंतर्गत प्रगणक डिम्पल सचदेवा को नगरायुक्त द्वारा सम्मानित कराया

दवा कारोबार पर नए सरकारी फरमान से व्यापारी नाराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आदेश वापस लेने की मांग

वेलकम इंडिया संवाददाता

बरेली। उत्तर प्रदेश में दवा कारोबार को लेकर शासन की ओर से जारी नए निदेर्शों का दवा व्यापारियों और चिकित्सक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए अलग वेबसाइट तैयार करने, दवाओं की उपलब्धता और साप्ताहिक स्टॉक का विवरण सार्वजनिक करने जैसी अनिवार्यताओं पर व्यापारियों ने आपत्ति जताई है। शुक्रवार को आईएमए, नीमा और थोक व फुटकर दवा कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल ने वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाकर शासनादेश पर तत्काल पुनर्विचार कराया जाए और इसे वापस लिया जाए। प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, शासन की ओर से एक



अक्टूबर 2026 को जारी निदेर्शों में दवा विक्रेताओं के लिए वेबसाइट तैयार करने और दवाओं की उपलब्धता व साप्ताहिक स्टॉक का विवरण सार्वजनिक करने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अस्पताल परिसरों में संचालित फार्मेसियों के लिए खरीद और बिक्री मूल्य प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि इन नियमों से छोटे और मध्यम स्तर के दवा कारोबारियों पर आर्थिक एवं तकनीकी दबाव बढ़ेगा। साथ ही उनकी व्यापारिक गोपनीयता भी प्रभावित हो सकती है।

दवा कारोबारियों ने कहा कि किसी दवा के खरीद और बिक्री मूल्य के अंतर को ही वास्तविक मुनाफा मानना उचित नहीं है। मेडिकल स्टोर के किराये, कर्मचारियों के वेतन, बिजली बिल, परिवहन, एक्सपायरी दवाओं और स्टॉक में फंसी पूंजी जैसे कई खर्च भी कारोबार का हिस्सा हैं। ऐसे में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखे बिना लाभ का आकलन करना व्यावहारिक नहीं होगा। व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि वे मरीजों को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने और मूल्य पारदर्शिता के विरोध में नहीं हैं। उनका सुझाव है कि प्रत्येक मेडिकल स्टोर के लिए अलग-अलग वेबसाइट अनिवार्य करने के बजाय सरकार या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की ओर से एक प्रमाणित केंद्रीय दवा मूल्य पोर्टल तैयार किया जाए। इससे मरीजों को दवाओं की कीमत और उपलब्धता की जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी तथा दुकानदारों पर अतिरिक्त तकनीकी बोझ भी नहीं पड़ेगा। बरेली रिटेल केमिस्ट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा कि मरीजों के हित और पारदर्शिता के नाम पर दवा कारोबारियों के वैध अधिकारों, गोपनीयता और सम्मान की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएम-एसपी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण

राजीव मोंगरा/

सहारनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शनिवार को प्रस्तावित सहारनपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, मंच, बैठक व्यवस्था तथा आमजन की आवाजाही से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम



स्थल के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। साथ ही मुख्यमंत्री के आगमन और कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए विभागों के बीच समन्वय बनाकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था और यातायात संचालन पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए प्रशासनिक और पुलिस महकमे में सक्रियता बढ़ गई है। अधिकारी लगातार तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जा सके। प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का प्रयास है कि मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए सभी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है।

समरसता यात्रा का सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान के नेतृत्व में हुआ स्वागत

सीकरी कला स्थित श्रीरविदास मंदिर में पुष्प एवं माल्यार्पण कर यात्रा को किया गया रवाना

अनिल वशिष्ठ



मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के 650वें जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में जालंधर से वाराणसी तक निकाली जा रही भव्य समरसता यात्रा का मोदीनगर पहुंचने पर राष्ट्रीय लोक दल के नेतृत्व में जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। यात्रा के साथ चल रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्य हरेंद्र जाटव जी एवं लाल सिंह का मोदीनगर आगमन पर फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम की अगुवाई बागपत लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय डॉ. राजकुमार सांगवान ने की।

इस अवसर पर विधायक श्रीमती मंजू शिवाच, राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष रामपाल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष सहकारिता चेयरमैन अमरजीत सिंह बिड्डी' जिला अध्यक्ष भाजपा चैन पाल सिंह, दिनेश सिंघल पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा, पवन सिंघल, देवेंद्र चौधरी वरिष्ठ भाजपा नेता, योगेश फफराना, विनोद जाटव वैशाली (अध्यक्ष, नगर पालिका) मनोज राठी जिला उपाध्यक्ष, विनोद गौतम (पूर्व सभासद एवं जिला उपाध्यक्ष) आलोक चौधरी विधानसभा अध्यक्ष, विराट सांगवान, नरेंद्र जाटव जी (पूर्व जिला अध्यक्ष), ललित सेन (सभासद), अमित कुमार,अशोक जाटव, ब्रह्मसिंह जाटव, ब्रह्मपाल जाटव, शीशराम जाटव, आदित्य गौतम एडवोकेट, सहित भाजपा के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित एवं अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक प्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने संपूर्ण मानव समाज को समानता, सामाजिक न्याय, भाईचारे, प्रेम और समरसता का संदेश दिया। उनका विचार था कि समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो तथा प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर प्राप्त हों। आज आवश्यकता है कि हम उनके विचारों को आत्मसात करते हुए सामाजिक एकता और सद्भाव को और अधिक मजबूत करें। उन्होंने समरसता यात्रा के मोदीनगर आगमन पर सभी अतिथियों, सामाजिक संगठनों, गणमान्य नागरिकों एवं कार्यकताओं का आभार व्यक्त किया।

नॉर्थ मेट्रो स्टेशन पर स्वागत कार्यक्रम के उपरांत सभी उपस्थित साथी समरसता यात्रा में शामिल हुए। इसके बाद सीकरी कला स्थित श्री रविदास मंदिर पहुंचकर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की प्रतिमा पर पुष्प एवं माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा यात्रा को वाराणसी के लिए आगे रवाना किया गया।

सिवालखास विधानसभा क्षेत्र के ठाकुर बाहुल्य ग्राम कालंदी में राष्ट्रीय लोकदल की संगठनात्मक बैठक संपन्न



वेलकम इंडिया संवाददाता

मेरठ। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के ठाकुर बाहुल्य ग्राम कालंदी में राष्ट्रीय लोकदल की संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सिपस्टर शर्मा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय प्रदेश महासचिव रणवीर दहिया उपस्थित रहे। बैठक का संचालन क्षेत्रीय सचिव रवि भारत चिकारा ने किया। बैठक में एनडीए सरकार की नीतियों, राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका, संगठन की मजबूती एवं पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि रणवीर दहिया ने उपस्थित लोगों से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं से आगामी 30 नवंबर तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने एवं वोट बनवाने की अपील की, ताकि सभी पात्र युवा अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इस अवसर पर ठाकुर नितिन सोम, ठाकुर उपदेश राणा, ठाकुर यशवंत, ठाकुर रंजीत सिंह, ठाकुर इंद्राज सोम, ठाकुर जवर सिंह सोम, ठाकुर प्रेमपाल सोम, ठाकुर वेदपाल सिंह, ठाकुर संजय सिंह, ठाकुर महेंद्र दरोगा ठाकुर लीलू एवं ठाकुर संदीप जी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने संगठन के विस्तार और जनसेवा के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया।

यात्रियों की सुविधा ताक पर, विज्ञापन से कमाई में जुटी कंपनी! बिना बेंच लगाए ही लगा दिए विज्ञापन

शहर में 100 नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी के बीच यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए जा रहे यात्री शेड में ही लापरवाही सामने आने लगी है। नगर निगम ने शहर में 69 यात्री शेड बनाने का ठेका निजी कंपनी को दिया है, लेकिन कंपनी यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने से पहले ही विज्ञापन लगाकर कमाई करने में जुट गई है।

कई स्थानों पर यात्री शेड तो बना दिए गए हैं, लेकिन उनमें बैठने के लिए बेंच या कुर्सियों की व्यवस्था तक नहीं की गई है। इसके बावजूद विज्ञापन लगा दिए गए हैं। ऐसे में बसों का इंतजार करने वाले यात्रियों को खड़े रहकर ही समय बिताना पड़ रहा है। नगर निगम की योजना के तहत निजी कंपनी को अपने खर्च पर यात्री शेड बनाने हैं। इसके बदले कंपनी को इन शेड पर विज्ञापन लगाने और उससे आय अर्जित करने की अनुमति दी गई है। हालांकि निगम की शर्तों के मुताबिक विज्ञापन लगाने से पहले यात्रियों के बैठने की समुचित व्यवस्था करना जरूरी है। इसके लिए बेंच या कुर्सियां लगाई जानी थीं, ताकि महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों को परेशानी न हो। शहर में अब तक 20 से अधिक यात्री शेड बनाए जा चुके हैं। शुरूआत में कंपनी ने प्रमुख और अधिक आवाजाही वाले स्थानों को प्राथमिकता दी है, जहां यात्रियों के साथ विज्ञापन देखने वालों की संख्या भी अधिक रहती है। यही वजह है कि शेड तैयार होते ही विज्ञापन लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया, जबकि यात्रियों के बैठने की व्यवस्था अधूरी है।

कलछीना में वोट बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत खाट चौपाल आयोजित

वेलकम इंडिया संवाददाता



मोदीनगर। भोजपुर ब्लॉक के ग्राम कलछीना में कांग्रेस की ओर से वोट बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत खाट चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं।

चौपाल का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने किया, जबकि कार्यक्रम के संयोजक जिला महामंत्री डॉ. ताहिर तोमर रहे। खाट चौपाल के दौरान ग्रामीणों के बीच लोकतंत्र, मताधिकार और मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि रागिनी नायक ने ग्रामीणों से घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच करने, अपने नाम की पुष्टि करने तथा जिन लोगों के नाम सूची में नहीं हैं, उनके नाम जुड़वाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार नागरिकों की महत्वपूर्ण ताकत है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहना चाहिए।

कार्यक्रम में किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक जोगेश नेहरा, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आशीष शर्मा, जिला महामंत्री नंदकिशोर शर्मा तथा भोजपुर ब्लॉक अध्यक्ष भीष्म सिंह दूहन सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा चांदवीर चौधरी, खाली तोमर, समर तोमर, पप्पू, नजाकत अली, मुकम्मल अब्बास, शाहिद, रूबी मलिक, सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकताओं एवं ग्रामीणों ने चौपाल में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया।

कांग्रेस कार्यकताओं ने अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने और लोगों को उनके मताधिकार के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया।

धूल पर नगर निगम का डबल अटैक, सड़कों की सफाई के साथ हो रही पानी से धुलाई, पांचों जोन में अभियान तेज

वेलकम इंडिया संवाददाता



गाजियाबाद। शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को सुधारने और सड़कों से उड ाने वाली धूल पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने सफाई अभियान तेज कर दिया है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए अब केवल पानी का छिड़काव ही नहीं, बल्कि सड़कों पर जमी धूल को हटाने और प्रमुख मार्गों की धुलाई कराने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। नगर निगम की ओर से पांचों जोन में रोस्टर के अनुसार धूल मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए आधुनिक मशीनों, वाटर स्प्रिंकलर, लोडर और सफाई मित्रों की मदद ली जा रही है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने संबंधित विभागों को अभियान में तेजी लाने और नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग और निर्माण विभाग को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोडर और सफाई मित्रों के माध्यम से सड़कों के किनारे तथा मुख्य मार्गों पर जमा धूल हटाई जा रही है।

केशव शर्मा का शूटिंग में शानदार प्रदर्शन गोल्ड मेडल हासिल कर किया मुरादनगर का नाम रोशन

शूटिंग चैंपियनशिप में केशव शर्मा ने साधा सटीक निशाना, यूथ वर्ग में जीता गोल्ड मेडल

वेलकम इंडिया संवाददाता



मोदीनगर। प्रतिभा, मेहनत और लगन के दम पर रालोद नेता अरुण शर्मा के पुत्र मुरादनगर के होनहार छात्र केशव शर्मा ने शूटिंग के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में केशव ने अपने सटीक निशाने से प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए यूथ वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जानकारी के अनुसार स्पैरो शूटिंग एकेडमी गंगनहर मुरादनगर द्वारा 19 से 22 नवंबर 2026 तक स्पैरो शूटिंग चैंपियनशिप-2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी निशानेबाजी का कौशल दिखाया। इसी प्रतियोगिता में पूर्ण ज्ञानांजलि स्कूल में कक्षा 11वीं के छात्र केशव शर्मा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के यूथ वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। केशव शर्मा राष्ट्रीय लोकदल के मुरादनगर विधानसभा अध्यक्ष पंडित अरुण शर्मा के पुत्र हैं। बेटे की इस शानदार उपलब्धि से परिवार, स्कूल और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। केशव की सफलता को उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम माना जा रहा है। केशव की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि यदि लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प और निरंतर अभ्यास हो तो सफलता अवश्य मिलती है। शूटिंग जैसे एकाग्रता और धैर्य वाले खेल में स्वर्ण पदक जीतना उनकी प्रतिभा और कठिन परिश्रम को दर्शाता है केशव शर्मा की इस उपलब्धि पर परिवारजनों, शिक्षकों, मित्रों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। सभी ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वह भविष्य में भी इसी तरह शानदार प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। पंडित अरुण शर्मा के पुत्र केशव शर्मा की इस सफलता से मुरादनगर में खुशी की लहर है और उनकी उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए

वंडर डिक्लेयर लिमिटेड ने बेटी मानशी को दिया 1,01,000 का चेक

वैवाहिक जीवन के लिए दी शुभकामनाएं



गाजियाबाद(वेलकम इंडिया)। आर.के. ग्रुप की वंडर सीमेंट लिमिटेड की ओर से बेटियों के निर्माण की दिशा में बढ़ते कदम। कंपनी द्वारा आयोजित स्पर्श कन्यादान योजना के अंतर्गत 101000/- चेक स्वरूप उपहार वंडर सीमेंट लिमिटेड के मेसर्स मानसी ट्रेडर्स की सुपुत्री मानशी को गाजियाबाद के कंपनी के जोनल हेड उदित तिवारी, सेल्स अधिकारी विष्णु गुप्ता, इंजीनियर अनुपम रावत, बिजनेस रिटेलर के के. तलवार के द्वारा प्रदान किया गया एवं विवाह उत्सव में शामिल होकर वर वधू को उनके सुखमय जीवन की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान वंडर सीमेंट लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि स्पर्श कन्यादान योजना के तहत आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर बेटियों के सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कंपनी का उद्देश्य सामाजिक दायित्व निभाते हुए श आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में सहयोग करना है। मानशी के परिजनों ने वंडर सीमेंट के लिमिटेड के लिए इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया। कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य एवं एवं परिजन उपस्थित रहे।

आर्य समाज निवाड़ी द्वारा 19 वा वार्षिकोत्सव प्रारंभ

वेलकम इंडिया संवाददाता



मोदीनगर। आर्य समाज निवाड़ी द्वारा 19 वा वार्षिकोत्सव आज से प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम नगर पंचायत निवाड़ी में आर्य कृष्ण शास्त्री के निवास स्थान पर 3 दिन चलेगा। जिसमें दूर-दूर से आचार्य शास्त्रीगन पधारे हैं।आचार्य द्वारा सुबह शाम करीब 700 मत्रों के साथ यज किया जायेगा। वहां पर मौजूद अतिथियों का आर्य द्वारा स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में नगर वासियों व आसपास क्षेत्र के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

नगर पंचायत निवाड़ी में आचार्य व शास्त्री गानों का नगर पंचायत निवासियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। आचार्यों ने अपनी वाणी से अच्छे-अच्छे भजन कीर्तन किया जिससे पूरा माहौल मंद मुग्ध हो गया। आचार्य द्वारा भाकियू के राष्ट्रीय संरक्षक के बेटे रोहित त्यागी जो की 2 वर्षों से कुवैत में जॉब कर रहा है। उसको भी सम्मानित किया गया। फूलमाला पहनाकर और आर्य की किताबें देकर उसका सम्मान किया गया। आचार्य कृष्ण शास्त्री ने कहा कि ऐसे ही हमारे नगर पंचायत निवाड़ी का नाम रोशन करते रहे हम ऐसे ही बच्चों का प्रोत्साहन करेंगे।

जिन्होंने हमारे नगर पंचायत निवाड़ी का नाम रोशन विदेशो में भी किया है। बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने धर्म लाभ उठाया। कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन किसान सभा के राष्ट्रीय संरक्षक सत्येंद्र त्यागी, नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल त्यागी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष प्रवीण त्यागी, सचिन ठेकेदार, आचार्य कृष्ण शास्त्री, डॉक्टर ज्ञानोदय आर्य, आर्य सतीश कुमार, आर्य जितेंद्र एडवोकेट,आर्य सुबोध कुमार, आचार्य रविदास शास्त्री, आचार्य मुकेश शास्त्री, आचार्य विजयपाल कसाना,आचार्य सतवीर चौधरी, ओमपाल चौधरी, चेतन प्रजापति, विकास प्रजापति आदि बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

आठ टीमें, पांच जोन और निगरानी के दावे... फिर भी प्रदूषण पर लगाम बेअसर, वेद विहार की हवा रेड जोन में

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिले को पांच जोन में बांटकर आठ निगरानी टीमें गठित की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार होता नजर नहीं आ रहा है। ग्रेप के नियम लागू होने के बाद भी सड़कों पर उड़ती धूल, खुले में पड़ी निर्माण सामग्री, निर्माण स्थलों से उठता गुबार और फैक्ट्रियों से निकलता धुआं प्रदूषण नियंत्रण के दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बृहस्पतिवार को जिले का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 255 दर्ज किया गया, जबकि वेद विहार में एक्यूआई 355 पहुंचने से हवा रेड जोन में रही। प्रदूषण की रोकथाम के लिए 20 अक्टूबर से ग्रेप के पहले चरण की पाबंदियां लागू की गई थीं। इसके बाद दूसरे और तीसरे चरण की पाबंदियां भी लागू की गईं। निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए जिले को पांच जोन में बांटकर आठ टीमें गठित की गईं। अधिक प्रदूषित क्षेत्रों में दो-दो और कम प्रदूषित क्षेत्रों में एक-एक टीम को जिम्मेदारी दी गई। इन टीमों को ग्रेप के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात में खास बदलाव नहीं दिख रहा है।

जोन-एक में साहिबाबाद, मोहननगर, कौशांबी, वैशाली, इंदिरापुरम, खोड़ा, राजेंद्र नगर और अर्थला को शामिल किया गया है। जोन-दो में लोनी, आर्य नगर, रूप नगर और ट्रानिका सिटी हैं। मोदीनगर, मुरादनगर, दुहाई, मेरठ रोड और राजनगर एक्सटेंशन जोन-तीन में आते हैं। बीएस रोड, एसएस जीटी रोड, कविनगर और पांडव नगर जोन-चार में शामिल हैं। वहीं सिद्धार्थ विहार, वेब सिटी, आदित्य सिटी, जयपुरिया सनराइज, डासना और हापुड़ जोन-पांच में रखे गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार बृहस्पतिवार को वेद विहार का एक्यूआई 355 दर्ज किया गया।

2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य, भोजपुर में दिलाई गई शपथ









वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने और समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को विकास खंड भोजपुर स्थित शहीद भगत सिंह सभागार में बाल विवाह मुक्त अभियान के दो वर्ष पूरे होने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉ. हिमानी अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। विशिष्ट अतिथि मोदीनगर विधायक डॉ. मंजू सिवाच ने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की जानकारी देते हुए बताया कि विवाह के लिए बालिका की न्यूनतम आयु 18 और बालक की 21 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग करने वालों के खिलाफ दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आमजन को बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान कन्या जन्मोत्सव मनाते हुए 11 नवजात बालिकाओं के परिवारों को सम्मानित किया गया और बेबी किट वितरित की गईं। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख सुचेता सिंह, लोकेन्द्र सिंह, स्वाति पाठक, डॉ. विक्रम और अंजना चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

एक ही छत के नीचे मिलीं परिवहन विभाग की सेवाएं, गाजियाबाद में लगा द्वितीय परिवहन मेला



वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। संभागीय परिवहन कार्यालय, गाजियाबाद के सारथी भवन में शुक्रवार को द्वितीय परिवहन मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले का उद्देश्य आमजन और वाहन स्वामियों को परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर सरल, सुगम और त्वरित रूप से उपलब्ध कराना रहा।

मेले में बकाया वाहन कर जमा कराने, वाहन डेटाबेस में मोबाइल नंबर अपडेट कराने, नए वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट व नवीनीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंस सहित विभिन्न सेवाओं के लिए विशेष काउंटर लगाए गए। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने आवेदकों को मौके पर ही सेवाएं उपलब्ध कराईं।

इस दौरान वाहन स्वामियों को बकाया कर समय से जमा करने और वाहन डेटाबेस में मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से अपडेट कराने के प्रति जागरूक किया गया। मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर सेवाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह, संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) विवेक कुमार खरवार सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन कर पारदर्शी और समयबद्ध परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ राजस्व संग्रह बढ़ाने के प्रयास जारी रहेंगे।

ऑपरेशन कन्विक्शन में शानदार काम करने वालों को पुलिस आयुक्त ने किया सम्मानित, 39 दोषियों को उम्रकैद





वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। कमिश्नरेट गाजियाबाद में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर, सनसनीखेज और महिला संबंधी अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने वाले अभियोजन अधिकारियों, कन्विक्शन सेल के पुलिसकर्मियों और कोर्ट पैरोकारों को पुलिस आयुक्त ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने सभी का उत्साहवर्धन करते हुए भविष्य में भी पूरी निष्ठा और लगन के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

पुलिस आयुक्त के निर्देशन में 1 जुलाई 2025 को कमिश्नरेट में कन्विक्शन सेल का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य शातिर और पेशेवर अपराधियों को न्यायालय से अधिकाधिक सजा दिलाना है। सेल द्वारा अभियोजन अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर चिन्हित गंभीर एवं महिला संबंधी अपराधों में मजबूत पैरवी की जा रही है। इसी का परिणाम है कि विभिन्न थानों से संबंधित मामलों में प्रभावी पैरवी के चलते अब तक 39 दोषियों को आजीवन कारावास, 13 को 20 वर्ष के कारावास तथा 17 दोषियों को 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दिलाई गई है। वर्ष 2026 में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अखिलेश कुमार, एडीजीसी गिर्राज सिंह भाटी, किरनपाल, आदेश त्यागी, सुनील कौशिक, नितिन शर्मा, ममता गौतम और रवि शर्मा सहित विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट उत्कर्ष वत्स, हरीश कुमार और सतीश कुमार शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा प्रभारी कन्विक्शन सेल डॉ. नीरज सिंह तोमर, मुख्य आरक्षी सत कुमार, उषा, प्रवेश पाल, रेनू, आरक्षी प्रताप सिंह तथा विभिन्न थानों के कोर्ट पैरोकारों को भी सम्मानित किया गया। इनमें कविनगर, टीला मोड़, विजयनगर, मसूरी, लोनी, मुरादनगर, इंदिरापुरम और मोदीनगर थानों के पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस आयुक्त ने सभी को इसी प्रकार अपराधियों को सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी जारी रखने के निर्देश दिए।

मतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए घर-घर पहुंच रहे अधिकारी, 28-29 नवंबर को विशेष अभियान



- मोदीनगर में एसडीएम कोमल पंवार ने किया सत्यापन कार्यों का निरीक्षण, पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर जोर

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 के तहत मतदाता सूची को शत-प्रतिशत शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए जिले में घर-घर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। मंडलायुक्त मेरठ मंडल एवं रोल ऑब्जर्वर भानु चंद्र गोस्वामी तथा जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मांडड़ के निर्देश पर ईआरओ और एईआरओ अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

इसी क्रम में एसडीएम मोदीनगर कोमल पंवार ने विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर पहुंचकर सत्यापन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने बीएलओ के कार्यों की प्रगति जांचने के साथ नागरिकों से संवाद कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और विवरण में संशोधन की जानकारी ली।

अधिकारियों को नए मतदाताओं का पंजीकरण, प्राप्त प्रपत्रों का समयबद्ध डिजिटाइजेशन और दोहरी एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन के अनुसार 28 एवं 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे। इस दौरान सभी बीएलओ अपने निर्धारित बूथों पर मौजूद रहकर नए मतदाताओं का पंजीकरण, दावे-आपत्तियां और संशोधन संबंधी आवेदन प्राप्त करेंगे। प्रशासन ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं सहित छूटे हुए पात्र नागरिकों से अभियान में शामिल होकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है।

डासना एनएच-24 पर धान से भरा ट्रक खाई में गिरा, चालक केबिन में बुरी तरह फंसा

फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर चालक को सुरक्षित निकाला, अस्पताल में कराया भर्ती



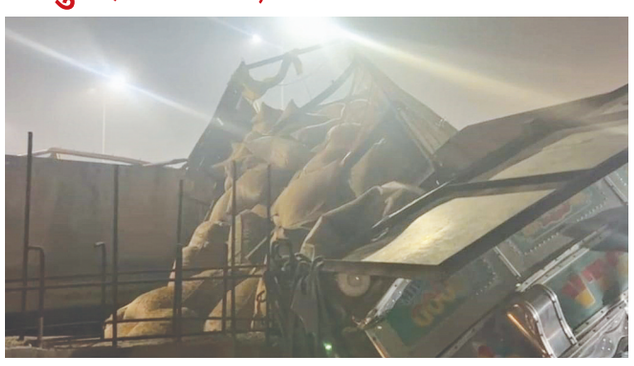

कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। डासना एनएच-24 के पास शुक्रवार सुबह धान से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। हादसे के दौरान ट्रक में चालक और हेल्पर सवार थे। हेल्पर किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आया, जबकि चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल फायर टैंकर और क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल के साथ मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने कॉम्बी टूल, हाइड्रोलिक उपकरणों और अन्य रेस्क्यू संसाधनों की मदद से एसडीआरएफ के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। इसके बाद एंबुलेंस से उसे नजदीकी अस्पताल भेजा गया। ट्रक का नंबर यूपी-13-सीटी-4072 है। चालक की पहचान अजब सिंह निवासी गेभा जमीराबाद, बुलंदशहर तथा हेल्पर सतीश पुत्र मेघ सिंह निवासी राधा नगर बाईपास, बुलंदशहर के रूप में हुई। मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद फायर यूनिट वापस फायर स्टेशन कोतवाली पहुंची।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को मिली नई कमान, लक्ष्मी सिंह होंगी नई पुलिस कमिश्नर

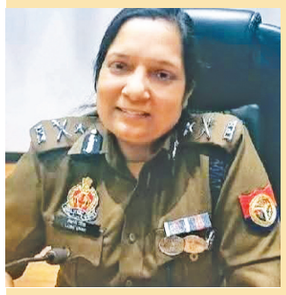



वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को नई पुलिस कमिश्नर मिल गई हैं। गौतमबुद्धनगर की पुलिस कमिश्नर रहीं वर्ष 2000 बैच की वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह को गाजियाबाद का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं, गाजियाबाद के मौजूदा पुलिस कमिश्नर जे. रविन्द्र गौड़ को गौतमबुद्धनगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रदेश सरकार की ओर से जारी तबादला सूची में कुल 28 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इस फेरबदल में दोनों कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्तों की जिम्मेदारियों की अदला-बदली हुई है। लक्ष्मी सिंह अब गाजियाबाद में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगी।

वहीं, वाराणसी के पुलिस कमिश्नर रहे मोहित अग्रवाल को प्रयागराज और किरण एस. को वाराणसी का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके अलावा लखनऊ, बरेली समेत प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी नई तैनाती की गई है। लक्ष्मी सिंह की नियुक्ति के बाद अब गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की कमान उनके हाथों में होगी।

राजनगर एक्सटेंशन की सड़कें होंगी गड्ढामुक्त और धूलमुक्त, जीडीए उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण

गुणवत्ता से समझौता नहीं, सड़कों की मरम्मत और सफाई के साथ हरित पट्टियों के रखरखाव के दिए निर्देश





वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। राजनगर एक्सटेंशन में बेहतर सड़क और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जीडीए उपाध्यक्ष ने शुक्रवार को क्षेत्र की निर्मित, निमार्णाधीन और प्रस्तावित सड़कों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण की गुणवत्ता, गड्ढों की मरम्मत, धूल नियंत्रण, सेंट्रल वर्ज और हरित पट्टियों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सड़कों को गड्ढामुक्त, धूलमुक्त और अवरोधमुक्त बनाया जाए।

निमार्णाधीन सड़कों की सतह समतल रखी जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। पुरानी सड़कों पर गड्ढों और टूट-फूट को तत्काल ठीक कराया जाए। नियमित सफाई और पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाए। सड़कों पर निर्माण सामग्री और मलबा न रखा जाए। सेंट्रल वर्ज में पेड़-पौधों की छंटाई, सिंचाई और देखभाल भी नियमित हो।

उपाध्यक्ष ने कहा कि बेहतर सड़क अवसंरचना, स्वच्छ वातावरण और सुगम यातायात व्यवस्था प्राधिकरण की प्राथमिकता है। सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे कराए जाएं।

अब मशीन बताएगी चलने का सही तरीका, फिजियोथेरेपी में नई तकनीक से होगा बीमारियों का सटीक आकलन

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। किसी व्यक्ति के चलने का तरीका भी उसकी शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकता है। अब आधुनिक तकनीक की मदद से चाल, शरीर के संतुलन और जोड़ों की गतिविधियों का वैज्ञानिक तरीके से विस्तृत विश्लेषण करना संभव हो रहा है। इसी तकनीक और उसके चिकित्सकीय उपयोगों से फिजियोथेरेपी के विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए आईटीएस फिजियोथेरेपी कॉलेज, मुरादनगर में शुक्रवार को 'गेट ऑन मोशन एनालिसिस सिस्टम का प्रदर्शन' विषय पर विशेष व्याख्यान एवं प्रायोगिक प्रदर्शन आयोजित किया गया। आईटीएस दी एजुकेशन ग्रुप के वाइस चेयरमैन अर्पित चड्ढा के मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायी नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में गेट ऑन मोशन एनालिसिस सिस्टम के प्रोडक्ट हेड सिद्धार्थ हंस मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. एम. थंगराज ने उनका स्वागत किया। इस दौरान सिद्धार्थ हंस ने विद्यार्थियों को इस आधुनिक प्रणाली की कार्यप्रणाली और फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में इसके उपयोगों की विस्तार से जानकारी दी।

28 और 29 नवंबर को चलेगा मतदाता सूची सुधार का विशेष अभियान, बीएलओ रहेंगे सक्रिय

- पात्र युवाओं और नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मिलेगा मौका, डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश



वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर-2027) के तहत गाजियाबाद में 28 और 29 नवंबर को मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं संशोधन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए हैं।

अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन और सत्यापन के कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं और अब तक मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं करा सके पात्र नागरिकों को जागरूक कर आवेदन के लिए प्रेरित किया जाएगा।

डीएम ने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना प्राथमिकता है। कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

ऑपरेशन प्रहार: मसूरी और भोजपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार गांजा तस्कर गिरफ्तार





वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। जिले में नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत मसूरी और भोजपुर पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए चार गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 18 किलो 136 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है।

मसूरी पुलिस ने 27 नवंबर को चेकिंग के दौरान नाहल झाल से कल्लूगढ़ी-नाहल जेल लिंक रोड पर नरेन्द्र निवासी निडौरी और सुबोध निवासी मोहिद्दीनपुर ढबारसी को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 9 किलो 130 ग्राम गांजा बरामद हुआ।

वहीं, भोजपुर पुलिस ने 26 नवंबर को दतैड़ी चौराहे के पास चेकिंग के दौरान दिनेश उर्फ दुनेश और पुष्पेंद्र निवासी हैदरनगर नगोला, हापुड़ को गिरफ्तार किया। इनके पास से 9 किलो 6 ग्राम गांजा बरामद हुआ। दोनों मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रही है।

शौलाना में नि:शुल्क नेत्र जांच शिविर, 150 ग्रामीणों की जांच और 60 कंबलों का वितरण!







वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। वरिष्ठ नागरिक सेवासमिति, गाजियाबाद द्वारा वरदान नेत्र चिकित्सा सेवा संस्थान के कुशल चिकित्सकों के सहयोग से ग्राम शौलाना के प्रज्ञा आश्रम में ग्रामीण जनो के नेत्रों की गहन जांच हेतु एक कैंप का आयोजन किया गया ,जिसमें 150 ग्रामीणों की आंखों की जांच की गई 18 लोग ऑपरेशन के लिए योग्य पाए गए जिन्हें सदैव की भांति वरदान चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद ले जा कर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के पश्चात घर छोड़ने की व्यवस्था निशुल्क की जानी है। कैंप में जहां वरदान चिकित्सा संस्थान की ओर से कुशल डॉक्टर्स की टीम मौजूद रही।



वही प्रज्ञा आश्रम के मुख्य व्यवस्थापक, श्री राम किशन जी की देखरेख मे सफल आयोजन किया गया। शौलाना ग्राम के निकट के अन्य ग्रामो के गरीब ग्रामीण निवासीगण को समिति की ओर से 60 ऊनी कम्बलो का वितरण किया गया। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति की ओर से डॉक्टर जे एल रैना संरक्षक आर के गुप्ता, अध्यक्ष वी पी रस्तोगी उपाध्यक्ष, हरिपालसिह महासचिव रमेश अरोड़ा, एल डी शर्मा डी के शर्मा एम बी भारद्वाज, एस के नन्दा ठाकुर दास सैनी राकेश कुमार गुप्ता ए के गुप्ता महेश चौधरी वी पी सिंह राजश्री रैना मिथलेश बंसल सरिता गुप्ता रेखा रस्तोगी राजेश गर्ग शोभ नाथ राय कुसुम लता गुप्ता बी जी शर्मा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया।